Publication Date 01.01.2025
Postal Registration No. G/CHD/0096/2024-26
Registrar of Newspapers of India
Regd. No. 46809/70 I Total Pages 52
Posted at MBU Chandigarh 1st of Every Month

हरियाणा सहकारी प्रकाश

Haryana Sahkari Parkash

सहकार से समृद्धि

वर्ष : 56 | अंक 01 | 1 जनवरी, 2025 | वार्षिक मूल्य : 500/- | प्रति कापी : 50/-

21 नवंबर, 2024 को लेज़र वैली ग्राउंड, सैक्टर–29, गुरूग्राम में 71वें राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह के समापन समारोह में जनता का अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, श्री नायब सिंह सैनी व सहकारिता मंत्री डॉ0 अरविंद कुमार शर्मा ।

HARCOFED
Bays No. 49-52, Sector - 2, Panchkula
https://www.harcofed.org.in
harcofed@ymail.com

71वां सहकारिता सप्ताह 2024 (समापन समारोह)- गुरुग्राम

राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह समारोह 2024 - रोहतक

एवं पर्यटन मंत्री, हरियाणा
15 नवम्बर, 2024

माननीय सहकारिता,
विरासत एवं पर्यटन

राज्य स्तरीय समारोह
सहकारिता सप्ताह 2024
RESERVED SEAT

सम्पादकीय

सहकार से समृद्धि

सहकार से समृद्धि पहल एक परिवर्तनकारी प्रयास है, जिसका उद्देश्य भारत की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में सहकारी समितियों की क्षमता का उपयोग करना है। इसका नेतृत्व केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय कर रहा है।

सहकारी क्षेत्र देश के मूल के करीब रहा है। देश में किसानी और सहकारिता आंदोलन रोजगार देने का एक प्रमुख ज़रिया है, इसीलिए सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने, सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने, पारदर्शिता लाने, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण करने, प्रतिस्पर्धी सहकारी समितियां बनाने और देश भर में जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करने के लिए, सरकार 'सहकार से समृद्धि' के तहत कार्रवाई कर रही है तथा उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, भारत अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न पहल कर रहा है जैसे –

- प्राथमिक सहकारी समितियों को पारदर्शी और आर्थिक रूप से जीवंत बनाना (14 पहल)
- शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को मजबूत बनाना (9 पहल)
- आयकर अधिनियम में सहकारी समितियों को राहत (6 पहल)
- सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार (4 पहल)
- राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई बहु–राज्य सोसायटी (3 पहल)
- सहकारिता में क्षमता निर्माण (3 पहल)
- 'व्यापार करने में आसानी' के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग (2 पहल)

इसके अतिरिक्त सहकारिताओं ने आर्थिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी कर विकास के स्तम्भ के रूप में पहचान बनाई है। यह गौरवमयी इतिहास की लम्बी गाथा है जो सभी सहकारों के हौंसले बुलन्द करती है। इसलिए हमारे समाज का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो सहकारिता से प्रभावित न हो।

वर्तमान में सहकारिताएं सक्षम है और सभी समस्याओं का एक मात्र विकल्प भी सहकारिताओं के पास ही है। इसे अब कर दिखाने के लिये हम सभी को मिल–जुल कर समर्पित भावना से कार्य करना होगा।

भारत में सहकारी समितियों का भविष्य आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मकता की कल्पना करता है। सहकारी समितियाँ आधुनिक प्रथाओं, सुदृढ़ शासन और वित्तीय व्यवहार्यता को अपनाएँगी। वे वाणिज्यिक फर्मों के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करेंगी और भारत के आर्थिक विकास में योगदान देंगी।

हरियाणा प्रदेश ने **माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ''सहकार से समृद्धि''** का जिम्मा जोरों–शोरों से उठाया हुआ है और सहकारी संस्थाओं को अधिकाधिक महत्व दिया जा रहा है। इसके साथ–साथ हरकोफैड ने भी सहकारी शिक्षा, सहकारी सिद्धान्त एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता एवं सक्रिय सदस्यता के सफल प्रयासों को पूर्ण किया है और आगे भी सहकारिता के विशाल पथ पर सरपट दौड़ने की नई निितियों को साकार रूप देने का कार्य कर रहा है।

हरियाणा सहकारी प्रकाश

मुख्य संरक्षक

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
सहकारिता विभाग, हरियाणा

संरक्षक
राजेश जोगपाल, भा.प्र.से.
रजिस्ट्रार सहकारी समितियां,
हरियाणा

मुख्य सम्पादक
सुमन बल्हारा
प्रबन्ध निदेशक, हरकोफैड

सम्पादक
सौरव शर्मा

सुविचार

आप जोखिम लेने से भयभीत न हो, यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व करते हैं, यदि हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

– स्वामी विवेकानन्द

'हरियाणा सहकारी प्रकाश' में प्रकाशित लेखकों के विचारों के साथ हरकोफैड का सहमत होना आवश्यक नहीं है। यह लेखकों के अपने विचार हैं।

हरियाणा सहकारी प्रकाश की विज्ञापन दरें :–

क्र.सं.	विवरण प्रति प्रकाशन	रुपये
1.	पूरा पृष्ठ टाईटल रंगीन	30000/-
2.	पूरा पृष्ठ रंगीन	20000/-
3.	पूरा पृष्ठ श्याम–श्वेत	12000/-
4.	आधा पृष्ठ श्याम–श्वेत	6000/-

इस अंक में पढ़िए

सम्पादकीय	6
अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन	8
'विकसित भारत' के लिए राजनीति में आएं युवा	9
ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और किसान सशक्तिकरण के लिए	10
71वां सहकारी सप्ताह 2024 समापन समारोह - गुरुग्राम	11-14
राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह समारोह 2024 रोहतक	15-17
सहकारिता जागरूकता अभियान	18-22
हरियाणा में 500 हाई-टेक सीएम-पैक्स केंद्र बनाए जाएंगे	23
हैफेड शुगर मिल के 17 वें पिराई सत्र की शुरुआत	24-25
हरियाणा में 710 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण	26
दि हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लि. (हरको बैंक) चण्डीगढ़	27
शाहबाद चीनी मिल एवं लेबर फेडरेशन द्वारा सहकारी सप्ताह मनाया गया	27
स्वदेशी अपनाओ, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ	28
सहकारी संस्थाओं की गतिविधियां, उपलब्धियाँ एवं योजनाएं	29-32
हरको बैंक मुख्यालय में सोलर पैनल का उद्घाटन व लिफ्टों का शिला न्यास	33
नैनो उर्वरक जागरूकता अभियान-किसान सभा, गांव बलियाला - टोहाना	33
हरकोफैड की ओर से आयोजित लेख व ड्राइंग प्रतियोगिता	34
प्राथमिक सोसायटी का उद्देश्य किसानों को बढ़ावा देना व उन्हें विकसित करना	35
फसल को लेकर किसानों को किया जागरूक	35
ROLE OF COOPERATIVES IN 'VIKSIT BHARAT'	36-38
बापू आज भी प्रासंगिक हैं	39-40
विद्यार्थी भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन	40
पारंपरिक कृषि के मुकाबले जैविक कृषि के फायदे	41-43
बच्चे हमारे आचरण से सीखते हैं, उपदेश से नहीं	44
एसबीएम ने खोला कचरे से कमाई का रास्ता	45-46
प्रेस कतरनें	47-49
विज्ञापन	51

E-MAIL
harcofed@ymail.com
harcopress@gmail.com

Website
https://www.harcofed.org.in

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन

भारत के लिए सहकारिता संस्कृति का आधार
– पीएम

'भारत में हम सहकारी आंदोलन को नया आयाम दे रहे हैं' – पीएम

दिनांक 25 नवंबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का उद्‌घाटन किया है। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और इससे जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। 30 नवंबर तक चले इस आयोजन में 100 से ज्यादा देशों के 1,500 प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में वैश्विक सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने सहकारी आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ भी किया ।

इस कार्यक्रम में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे के और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका भी मौजूद रहे। सहकारी आंदोलन के विकास के लिए मंत्रालय की ओर से तीन साल में की गई 54 पहलों को लेकर भी इस आयोजन में विशेष इंतजाम किए गए, ताकि दुनिया भारत में सहकारिता के बढ़ते कदमों से परिचित हो सके।

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज जब मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं, तो मैं यह अकेले नहीं कर रहा हूं, मैं यह नहीं कर सकता। मैं आप सभी का किसानों, मछुआरों, स्वयं सहायता समूहों की 10 करोड़ महिलाओं, 8 लाख से अधिक सहकारी संस्थाओं की ओर से स्वागत करता हूं।

पीएम मोदी ने कहा, 'यह कॉन्फ्रेंस पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है। भारत में हम सहकारी आंदोलन को नया आयाम दे रहे हैं। यह कॉन्फ्रेंस भारत की भविष्य की सहकारी यात्रा के लिए आवश्यक जानकारी देगी। भारत के अनुभव वैश्विक सहकारी आंदोलन को 21वीं सदी के नए उपकरण और भावना प्रदान करेंगे दुनिया के लिए सहकारिता एक मॉडल है, भारत के लिए यह संस्कृति का आधार है, एक जीवनशैली है।

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2025 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने के लिए आभार व्यक्त किया।

'विकसित भारत' के लिए युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक प्रयासों से बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस तरह की भावना लोगों ने दिखाई थी 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे फिर से दिखाने की जरूरत है।

श्री मोदी ने अपने मासिक 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम में कहा कि उनकी ओर से स्वतंत्रता दिवस पर बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले एक लाख युवाओं के राजनीति में शामिल कहा है कि वंशवाद की राजनीति नई प्रतिभा को दबा देती है। उन्होंने कहा, श्इस साल मैंने लाल किले से बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले एक लाख युवाओं को राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ने का आह्वान किया है। मेरी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा, राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन युवाओं को बस सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है। श्री मोदी ने कहा, 'इस विषय पर मुझे देशभर के युवाओं के पत्र भी मिले हैं। सोशल मीडिया पर भी इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। लोगों ने मुझे कइ तरह के सुझाव भेजे हैं। कुछ युवाओं ने अपने पत्रों में लिखा है कि ये वाकई उनके लिए अकल्पनीय है। अपने दादा या माता–पिता के पास राजनीतिक विरासत न होने के कारण वे चाहकर भी राजनीति में नहीं आ पाते थे। उन्होंने कहा कि कुछ युवाओं ने लिखा है कि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अच्छा अनुभव है ओर इसलिए वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार बन सकते हैं। उन्होंने कहा, कुछ युवाओं ने यह भी लिखा है कि परिरवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन कर देती है। कुछ युवाओं ने कहा कि ऐसे प्रयासों से हमारे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। मैं इस विषय पर सुझाव भेजने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं।

ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और किसान सशक्तिकरण के लिए हरियाणा में 500 हाई-टेक सीएम-पैक्स केंद्र बनाए जाएंगे

सीएम–पैक्स किसानों के लिए प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए होंगे वन–स्टॉप सेंटर – राज्यपाल

एफपीओ और पैक्स को अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाने के लिए 1 करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा – राज्यपाल

रबी सीजन 2023–24 में 49,000 किसानों को फसल मुआवजे के रूप में दिए 133.75 करोड़ रुपये

'ई–खरीद' पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों को मिला एमएसपी का लाभ, 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपये हस्तांतरित

चंडीगढ़, 13 नवंबर :– हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान राज्य सरकार अत्याधुनिक 500 सी.एम. पैक्स स्थापित करेगी, जो किसानों को प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सेवाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर्स का कार्य करेंगे।

इसके अलावा, कृषक समूहों और पैक्स को अनाज भण्डारण के लिए गोदाम बनाने हेतु एक करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। सरकार किसान उत्पाद संघ–एफपीओ और पैक्स जैसे सहकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए किसान कल्याण सरकार की नीतियों के केन्द्र में है। किसानों के हितों में निर्णय लेते हुए सरकार ने कुछ दिन पहले ही अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म किया है। इसके अलावा, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद की जाती है। इस साल मानसून देरी से आने के कारण किसान को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़े। इससे फसल की लागत बढ़ी। इसमें राहत के लिए राज्य सरकार ने सभी खरीफ फसलों के लिए हर किसान को 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस दिया है। ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है।

राज्यपाल ने कहा कि रबी सीजन–2023–24 में फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए भी 49,000 किसानों को 133.75 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मुआवजे के रूप में जारी की गई है। इसकी अलावा, सरकार ने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई–खरीद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में एम.एस.पी. पर फसल खरीद के 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपये डाले हैं।

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए बनाई जा रही नीतियां श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए प्रदेश की कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रही है। हमारा किसान ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो और उसकी आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियां बनाई जा रही हैं व अनेक निर्णय लिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज नकली खाद, बीज व कीटनाशक कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बन गये हैं। राज्य सरकार इन पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाएगी और किसानों को शत–प्रतिशत मुआवजा देना भी सुनिश्चित करेगी।

राज्यपाल ने कहा कि सिंचाई जल की कमी को देखते हुए कम पानी में उगने वाली फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार धान की जगह अन्य फसल बोने या खेत खाली रखने पर भी किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की राशि देगी। उन्होंने कहा कि पानी की कमी आज एक विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है। इसलिए सरकार पानी की एक–एक बूंद का इष्टतम उपयोग करने तथा वितरण में होने वाली पानी की बर्बादी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार जारी रखा जाएगा। (सूक्ष्म सिंचाई, 19716 तालाबों के जीर्णोद्धार, गन्दे पानी के उपचार एवं प्रबंधन की नीतियां जारी रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रावी–ब्यास नदियों के पानी का अपना वैध भाग प्राप्त करने और सतलुज–यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन मामलों में निरंतर ठोस पैरवी की जा रही है।

71वां सहकारी सप्ताह 2024
समापन समारोह - गुरुग्राम

विकास के लिए सहकारी समितियों से लागों को जुड़ने का किया आह्वान –

श्री नायब सिंह सैनी, मुंख्यमंत्री हरियाणा

रेवाड़ी में बनेगी देश की सबसे बड़ी सरसों तेल मिल और नारायणगढ़ में नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल होगी स्थापित –

श्री नायब सिंह सैनी, मुंख्यमंत्री हरियाणा

दिनांक 21 नवंबर, 2024 को लेज़र वैली ग्राउंड, सैक्टर–29, गुरुग्राम में 71वें राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह का समापन समारोह मनाया गया। इस राज्य स्तरीय भव्य आयोजन का माननीय मुख्यमंत्री, श्री नायब सिंह सैनी जी ने मुख्यातिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और सहकारिता की भावना एवं सामुदायिक विकास के महत्व को एक नई दिशा प्रदान की। सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता जी ने माननीय मुख्यातिथि महोदय का स्वागत किया। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ0 अरविंद कुमार शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और अतिथि के रूप में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह, सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष समेत गुरुग्राम के विधायक उपस्थित रहे।

श्री नायब सिंह सैनी ने अपने सम्बोधन में प्रदेशभर से आए सभी सहकारी बन्धुओं को 71वें राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह की बधाई दी एवं सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होने लोगों से विकसित भारत विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने के लिए सहकारी समितियों से सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होने घोषणा करते हुए कहा कि नारायणगढ़ में जल्द ही एक नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में एक आधुनिक सूरजमुखी तेल पिराई मिल स्थापित होगी और रेवाड़ी में भी देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल स्थापित की जाएगी। उन्होने कहा की सहकारी समितियां कृषि और ग्रामीण विकास व राष्ट्र की

अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह का आयोजन इस महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने और सहकारिता आंदोलन को ओर तेज करने का काम करता है। उन्होंने हरियाणा मे विभिन्न उत्पादों के लिए अमूल व अन्य की तहर एक एकीकृत ब्रांड बनाने का भी सुझाव दिया।

71वें राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह की थीम **विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका** पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन रखा है। उन्होने विश्वास व्यक्त किया कि **सहकार से समृद्धि** का मंत्र इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होने कहा कि विभिन्न प्रकार की सहकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 40 पहल की गई हैं। सभी 19 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने राज्यभर में 7 लाख से अधिक किसानों को रूपये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। इसके अलावा गोदम विकास के लिए 11 पैक्स केंद्रों का चयन किया गया है। उन्होने यह भी कहा कि प्रदेश में समय पर कर्ज की अदायगी करने वालों के लिए ब्याज राहत योजना के तहत 50 प्रतिशत की छूट दी है। अब तक 101 करोड़ रूपये की ब्याज राहत दी जा चुकी है।

उन्होने कहा कि सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति के सदस्यों की बेटियों की शादी के लिए कन्यादान योजना के तहत लाभ दिया जाता है। उनके मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 10 में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को 2100 रूपये और कक्षा 12 के लिए 5100 रूपये प्रदान किए जाते हैं। उन्होने बताया कि हैफेड की दुबई और अन्य देशों से बासमती चावल के निर्यात के लिए ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसमें 1200 करोड़ रूपये मूल्य का लगभग 1 लाख मीट्रिक टन चाल निर्यात किया गया है। हैफेड़ ने रेवाड़ी और नारनौल में नई तेल मिलें, साथ ही रादौर में हल्दी का प्लांट भी स्थापित किया है। रोहतक में 180 करोड़ रूपये की लागत से मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। उन्होने कहा कि राज्य की चीनी मिलें पूरी क्षमता से चल रही हैं, 360 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करके इस सीजन में 35 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है। पानीपत, रोहतक, करनाल, शाहबाद और गोहाना की सहकारी चीनी मिलों ने 2023–2024 के पेराई सीजन के दौरान राज्य पावर ग्रिड को 13 करोड़ यूनिट बिजली बेचकर 63 करोड़ रूपये कमाए हैं।

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहकारिता मेले का निरक्षण किया और समारोह में प्रदेश की सहकारी समितियों और पदाधिकारियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया। इन समितियों ने ग्रामीण ओर शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से न केवल आर्थिक सशक्तिकरण किया है, बल्कि सामूहिक प्रयासों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अग्रसर किया है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने मंच से प्रदेशभर से आये सहकार बन्धुओं का अभिनन्दन किया और 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होने मंच से राज्य भर में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होने कहा कि विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों से सहकारी ढांचे को मजबूत करने, स्थानीय समुदायों की क्षमताओं को बढ़ाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद मिली है। उन्होने बताया कि वर्तमान में हरियाणा में लगभग 33,000 कार्यात्मक सहकारी समितियां हैं, जिनमें लगभग 55 लाख लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गांव में एक सहकारी समिति या पैक्स होनी चाहिए।

सहकारिता विभाग, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, भा.प्र.से ने कार्यक्रम के मुख्यातिथि श्री नायब सिंह सैनी, मुंख्यमंत्री हरियाणा, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉ0 अरविंद कुमार शर्मा, सहकारिता मंत्री हरियाणा, विशेष अतिथि हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, श्री राव नरबीर सिंह, अतिथि गुरूग्राम के विधायकगण, श्री वेद फुंल्ला अध्यक्ष हरकोफैड, श्री हुक्म सिंह भाटी, अध्यक्ष हरको बैंक, श्री अमर पाल राणा, अध्यक्ष एच.एस.सी.ए.आर. डी.बी., श्री धर्मबीर सिंह डागर, अध्यक्ष शुगरफैड समेत सभी सम्मानित अतिथियों एवं प्रदेशभर से आये सभी सहकार बन्धुओं किसानों और सहकारी समिति के सदस्यों समेत प्रेस एवं छायाकर बंधुओं का समरोह में पंहुचने पर अभिवादन एवं स्वागत किया। उन्होंने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि 71वां राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह 14 से 20 नवंबर, 2024 तक हरियाणा राज्य में बड़ी धूम–धाम से मनाया गया और विकसित भारत के निर्माण में सहकारिताओं की भूमिका विषय के संदेश को जन–जन तक पहुंचाया। उन्होने सहकारिता विभाग में सहकार से समृद्ध के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चल रहे विकास कार्यों के विषय में सबको अवगत करवाया।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहकारिता विभाग हरियाणा के सलाहकार श्री सिद्धार्थ शंकर शर्मा को सहकारिता में उत्कृष्ट कार्य हेतु विशेष सम्मान से सम्मानित किया । सिद्धार्थ शर्मा को सरकारी और निजी क्षेत्र में 24 से अधिक वर्ष का अनुभव है। इन्होने नीवन रणनीतियों के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह पंजाब सरकार के सहकारिता विभाग में चार साल तक पेशेवर सलाहकार के रूप में सेवा कर चुके हैं। वर्तमान में सिद्धार्थ शर्मा हरियाणा के सहकारिता मंत्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

सांस्कृतिक प्रस्तुति : इस 71वें राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह के समापन में राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा के सुप्रसिद्ध युवा कलाकार एवं लोक गायक **श्रीमान सौरव अत्री** एवं उनके दल द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई जिसमें उन्होने प्रदेशभर से आए लोगों का मन मोह लिया। उन्होने कार्यक्रम में अपना स्वरचित स्वागत गीत प्रस्तुत कर मुख्यातिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत किया जिसने कार्यक्रम में जोश भर गया। प्रस्तुति के दौरान मुख्यमंत्री मंद–मंद मुस्कुराते रहे और सौरव अत्री की प्रशंसा की। सौरव अत्री द्वारा विशेष सहकारिता गीत जो उनकी खुद की रचना है ने समारोह में उपस्थित हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अत्री द्वारा गाए गए मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे भजन ने पंडाल को राम के रंग में भर दिया और पूरा पंडाल जय श्रीराम के उद्घघोष से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने अंत में सौरव अत्री व उनके कलाकारों को विशेष सम्मान से सम्मानित किया।

राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह समारोह 2024 रोहतक

सभी जिला मुख्यालयों पर विशेष कैम्प लगाकर दी जायेगी सहकारी योजनाओं की जानकारी

डॉ. अरविंद कुमार शर्मा, सहकारिता मंत्री, हरियाणा

15 नवम्बर 2024 को रोहतक के महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह समारोह बड़ी धुम–धाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां हरियाणा, श्री राजेश जोगपाल भा.प्र. से. द्वारा उनका स्वागत किया गया। सहकारिता गीत के साथ मुख्य अतिथि ने सहकारिता सतरगां झण्डा फहराया और रीबन काट कर सहकारिता मेले का शुभारंभ किया।

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने मंच से प्रदेशभर से आये सहकार बन्धुओं का अभिवादन स्वीकार किया और सभी को 71वें सहकारिता सप्ताह की शुभकामनाएं दी। अपने सम्बोधन में सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी करके प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने के साकार करना है। इसके लिये आने वाले समय में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विशेष कैम्प आयोजित किये जायेगें और जागरूकता अभियान भी चलाया जायगा जिसके माध्यम से लोगों को सहकारिता की जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी ताकि वे अपने ग्रुप बना कर सहकारिता से जुड़ कर स्वावलंबी बन सके। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा सहकारिता को बढ़ावा देने के लिये नई–नई योजनाएं लागू की जा रही है जिसका सीधा लाभ सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि महाराष्ट्र, गुजरात एवं कर्नाटक राज्य की तरज पर हरियाणा के प्रत्येक गांव में पैक्स स्थापित हों और अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़े और सहकारिता विभाग एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 मानकर काम करें। उन्होंने बताया कि दुबई और आबु–धाबी में भी हैफेड़ के प्रोडेक्ट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कुछ साल पहले तक हरियाणा के दुध के उत्पादों की मांग दुसरे प्रदेशों में थी लेकिन बीच में उनमें कुछ ठहराव सा लगा, अब उनको फिर से गति प्रदान करनी है। उन्होंने अपने सम्बोधन के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश भी दिये कि वे ऐसे प्रभावशाली ढ़ग से कार्य करे जिससे की आने वाले 6 महिनों के भीतर सहकारिता क्षेत्र में 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी हो।

उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में करीब 33 हजार सहकारी समितियां जिससे युवा, बुजुर्ग और महिलाओं सहित करीब 55 लाख सदस्य जुड़े हुए है। यह सभी लोग समूह बनाकर अपना काम करते है। उन्होंन कहा कि ऐसे छोटे–छोटे समूह बनाकर नागरिक सहकारिता क्षेत्र से जुड़कर पैट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी और वेयर हाउस तक स्थापित कर सकते है। इसके लिये सरकार द्वारा सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उन्होंने सहकार बन्धुओं से आग्रह भी किया कि सर्वप्रथम आप सहकारिता विभाग को गहराई से समझीये और जिसको सहकारिता का अर्थ समझ में आ जायेगा उसको काम करने की इच्छा होगी और वह लोगों को अपने साथ जोड़कर बढ़िया काम करेगा। सहकारिता सप्ताह समारोह के मौक पर माननीय मंत्री जी ने गुरू नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की सभी को बधाई दी और गुरू नानक देव जी को प्रणाम किया। उन्होंने बताया कि गुरू नानक देव जी ने सभी के भीतर सेवा की भावना जगाई। हम सभी के भीतर सेवा का भाव होना चाहिए क्योंकि सेवा से ही संगठन बनता है और अगर संगठन मजबूत होगा तो हम हर प्ररस्थिति का सामना कर सकेंगे। उन्होंने मंच से संदेश दिया कि कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है सेवा, हम सभी को जाति–पाति से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के मन में सेवा का भाव रखना है यदि सेवा का यह मूल मंत्र अमल में लाया जाये तो हमें कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां हरियाणा श्री राजेश जोगपाल, भा.प्र.से. ने कार्यक्रम में पहुंचे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ अरविंद कुमार शर्मा, सहकारिता मंत्री हरियाणा, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री वेद फुंल्ला अध्यक्ष हरकोफैड, अतिथि श्री हुकम सिंह भाटी, अध्यक्ष हरको बैंक, श्री अमर पाल राणा, अध्यक्ष एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी., श्री धर्मबीर सिंह डागर, अध्यक्ष शुगरफैड समेत सभी सम्मानित अतिथियों एवं प्रदेशभर से आये सभी सहकार बन्धुओं किसानों और सहकारी समिति के सदस्यों का अभिवादन एवं स्वागत किया। उन्होंने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि राज्य में सहकारिता सप्ताह का पर्व बड़ी धूम–धाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता एक जन–आंदोलन है और हम सभी के जीवन में आर्थिक शक्ति लाता है। हम सब मिलकर सहकारिता को अपनायें और सहकारिता के सतरंगें को गौरव से लहरायें उन्होंने सहकारिता विभाग की योजनाओं को विस्तार पूर्वक बताया।

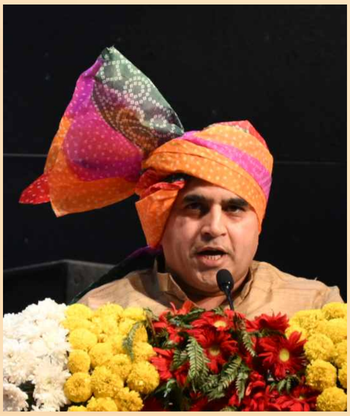

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे **श्री वेद फुंल्ला अध्यक्ष हरकोफैड** ने अपने सम्बोधन में कहा कि हरकोफैड सरकार और सहकारिता के बीच में एक सेतु की तरह काम करता है और सहकारिता की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर जाकर जन–जन तक पहुंचाने का काम करता है। उन्होंने सभी सहकार बन्धुओं से निवेदन किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोग एक समूह बनाकर के अपने जीवन यापन को ऊँचाई तक लेकर जाये और सहकारिता के माध्यम से पुरे हरियाणा में एक नई क्रान्ति लाये। इस आधुनिक समय में यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो सहकारिता ही एक माध्यम है जो

उसका हाथ पकड़के मुख्य धारा में लाने का काम कर सकता है।

श्री हुक्म सिंह भाटी, अध्यक्ष हरको बैंक ने अपने सम्बोधन में कहा कि हरियाणा राज्य सहकारिता के आन्दोलन में भारत के अग्रणीय राज्यों में गिना जाता है। हरको बैंक का मुख्य उद्देश्य सहकारिता की भावना को बढ़ावा देने के साथ–साथ प्रदेश के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है ताकि उनका जीवन उन्नत हो सके। हरियाणा प्रदेश में जो सुविधाएं व्यवासाइयक बैंकों के पास है वो सब सुविधाएं हरको बैंक और जिला सहकारी बैंकों के पास आज उपलब्ध है। हरको बैंक ने पैक्सों का कम्प्यूटीकरण भी किया है।

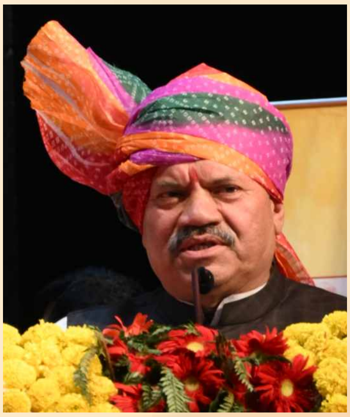

श्री अमर पाल राणा, अध्यक्ष एच.एस.सी.ए. आर.डी.बी., ने अपने सम्बोधन में कहा कि वर्तमान में सभी समितियों और राष्ट्रीय बैंकों के मुकाबले ग्रामीण विकास बैंक हरियाणा सबसे कम ब्याज सवा 6 प्रतिशत पर लोन उपलब्ध करवा रहा है। हमारी लगभग सारी शाखाएं कम्प्यूटराईज हो चुकी है और हम भविष्य में सभी सहकार बन्धुओं के सहयोग से बैंक को प्रगति के पथ पर ले जाने का कार्य करेंगे। जिससे सहकार से समृद्धि का सपना साकार होगा।

श्री धर्मबीर सिंह डागर, अध्यक्ष शुगरफैड ने अपने सम्बोधन में कहा कि शुगरफैड की सभी मिलें किसानों के हक में दिन प्रतिदिन कार्य कर रही है जिसके अन्तर्गत एक टोकन प्रणाली की शुरूआत की गई है जिससे किसानों को पहले जहां अपनी गन्ने की ट्राली खाली करने में चार–पांच दिन लगते थे वहीं अब टोकन प्रणाली के माध्यम से किसान 2 घंटे के अन्दर अपनी गन्ने की ट्राली मिल में खाली करके फारीक हो जाता है। पूरे भारत में हरियाणा अकेला एक ऐसा प्रदेश है जिसने किसानों का 100 प्रतिशत भुगतान समय पर कर दिया है और अगले वर्ष 2025 के लिये भी गन्ने का रेट निर्धारित कर दिया है। जो सर्वाधिक 400 रूपये प्रति क्विंटल है। शुगर मिल के माध्यम से किसानों का भला करने के लिये सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाये जा रहे है।

श्रीमती सुमन बल्हारा, प्रबन्ध निदेशक हरकोफैड ने कार्यक्रम के अंत में सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. अरविंद कुमार शर्मा सहकारिता मंत्री हरियाणा, सभी संस्थाओं के अध्यक्षों का कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने और सहकारिता क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिये विशेष आभार प्रकट किया। उन्होंने कार्यक्रम पहुंचे प्रदेशभर से आये सभी सहकार बन्धुओं से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहकारिता से जोड़े और सहकारिता की योजनाओं के महत्व को समझ कर जन–जन तक इनका प्रचार करें।

राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह समारोह में **हरियाणा के सुप्रसिद्ध लोक गायक श्री सौरव अत्री** द्वारा दिया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम आर्कषण का मुख्य केन्द्र रहा। सौरव अत्री एवं उनके ग्रुप ने अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिये एवं सभी सहकार बन्धुओं की वाह–वाही लुटी। उन्होंने विशेष रूप से सहकारिता पर अपना स्वरचित गीत प्रस्तुत किया जिसके द्वारा सहकारिता का संदेश दिया। उनकी बेहतरीन प्रस्तुति पर मुख्य अतिथि डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया।

सहकारिता जागरूकता अभियान

गोहाना (सोनीपत)

दिनांक 26.12.2024 को गोहाना में जिला स्तरीय सहकारिता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहकारिता जागरूकता अभियान का शुभारम्भ सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि यह जिला स्तरीय सहकारिता जागरूकता अभियान का आयोजन हरियाणा के सभी जिलों में आयोजित किया जायेगा जिसके अन्तर्गत जन–जन को सहकारिता के महत्व के विषय में बताया जायेगा और समाज के हर वर्ग विशेषकर युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ा जायेगा। इस अभियान को चलाने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि सहकार बन्धुओं को सहकारिता की योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें इनका भरपूर लाभ मिले और सहकार से समृद्धि का संकल्प साकार हो सके।

उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में काम करने के लिए 208 समूह को 4.16 करोड़ के लोन मंजूर किये और चैक बांटे। उन्होंने एक दिवसीय सहकारिता जागरूकता अभियान हर जिले में तीन दिन लगेगा। उन्होंने यह कहा कि सहकारिता के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने के काबिल बनाया जाये। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र की तरज पर हरियाणा में सहकारी समितियों के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। सहकारिता विभाग का लक्ष्य किसान महिला व युवाओं तक योजनाओं तक पहुंचाना है। माननीय मंत्री ने इस अवसर पर सोनीपत सैंट्रल को–ओपरेटिव बैंक द्वारा शुरू की गई म्हारे बुजुर्ग म्हारी धरोहर, विरागना लक्ष्मीबाई बचत योजना और नारी शक्ति उत्थान योजना का शुभारम्भ किया। उन्होंने सहकारिता विभाग में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं के उत्पाद सेना से लेकर विदेशों दुबई और आबुधाबी तक पहचान बना चुके हैं। सहकारी समितियों से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इनके उत्पादों को विदेशों में बढ़ावा दिया जायेगा जिससे इनके लाभ में बढ़ौतरी होगी। मुख्य अतिथि डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रर्दशनी में विभिन्न सहकारी संस्थाओं व स्वयं सहायता समूह के 20 स्टालों का अवलोकन किया और सहकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए

अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होनें लोगों से यह भी अपील की कि वह इस सहकारिता जागरूकता अभियान का फायदा उठाएं और सहकारिता विभाग की सभी योजनाओं की व्यक्तिगत रूचि लेकर जानकारी लें और उनसे रोज़गार स्थापित करने के अवसर भी ढूंढ़े।

रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा श्री राजेश जोगपाल भा.प्र.से. ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा, अतिथि सहकारी समितियों के अध्यक्ष और जिला सोनीपत के कोने–कोने से आए सहकार बन्धुओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 33 हजार समितियों से करीब 55 हजार लोग जुड़े है जिसमें युवा और बुजुर्ग सहित महिलाएं अपना स्वरोजगार स्थापित कर रही हैं। यह सभी लोग समूह बनाकर अपना काम कर रहे हैं। उन्होने कहा कि लाग छोटे–छोटे समूह बनाकर सहकारिता के क्षेत्र से जुड़कर पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी इत्यादि स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होनें कहा कि सहकारिता का मतलब है, समान उद्देश्य को हासिल करने के लिए कई लोगों या संस्थाओं का मिलकर काम करना।

इस अवसर पर गन्नौर के विधायक श्री देवेंद्र कादियान, सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा जी की पत्नी डॉ. रीटा शर्मा, सहकारी संस्थाओं के चेयरमैन, श्री हुकुम सिंह भाटी, श्री अमर पाल राणा, श्री धर्मबीर सिंह डागर, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा श्री राजेश जोगपाल, भा.प्र.से, हैफेड के प्रबन्ध निदेशक श्री मुकुल कुमार भा.प्र.से, गोहाना एस.डी.एम, श्रीमती अंजली श्रोतिरया, भा.प्र.से, गोहना चीनी मिल की एम.डी श्रीमती अंकिता वर्मा, ह.प्र.से अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, सुश्री पूनम नारा, श्रीमती सुमन बल्हारा, श्रीमती कविता धनखड़, श्री विरेन्द्र कुमार, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, श्री योगेश कुमार और श्री नरेश गोयल, गोकर्ण धाम के प्रमुख महंत बाबा कमल पुरी महाराज आदि मौजूद रहे।

गन्ने की उन्नत किस्मों व टिश्यू कल्चर पौधे में रहा किसानों का रूझान

चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल, आहुलाना के स्टाल पर किसानों का रूझान गन्ने की उन्नत किस्मों व टिश्यू कल्चर पौध की जानकारी लेने पर ज्यादा रहा। गन्ना विकास निरीक्षक संजय मलिक ने किसानों को बताया कि गन्ना की उन्नत किस्म से जहां वो अपनी पैदावार में बढ़ौतरी कर सकते है, वहीं टिश्यू कल्चर पौधे लगाने से बीमारी रहित गन्ना उत्पादन कर सकते है। इससे न केवल उनकी लागत में कमी आएगी, अपितु उत्पादन बढ़ने से फसल की पैदावार अच्छी होने से आर्थिक लाभ होगा। किसानों ने जैविक कीट प्रबंधन पर भी जानकारी प्राप्त की, ताकि सहयोगी कीट से फसल की गुणवता बेहतर हो सके।

सहकारिता जागरूकता अभियान में ऋण योजनाओं और स्टालों को लेकर आमजन ने दिखाया उत्साह

हैफेड की डीलरशिप को लेकर 35 लोगों को दी गई जानकारी

हैफेड स्टाल : सहायक विपणन अधिकारी अमित के पास 35 लोगों ने पहुंचकर हैफेड उत्पादों की डीलरशिप लेने की लेकर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इसके माध्यम से होने वाले लाभ की जानकारी भी प्राप्त की। यही नही वर्तमान में हैफेड उत्पाद कहां–कहां उपलब्ध रहेंगे, इसको लेकर भी आमजन में उत्सुकता रही।

कृषि उपकरणों पर सामान्य ब्याज दर के ऋण में लोगों की रही दिलचस्पी

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के स्टाल पर शनिवार को 21 ऋण के इच्छुक पहुंचे। स्टाल प्रतिनिधि ने बताया कि बैंक कृषि उपकरणों ट्रैक्टर, ट्राली आदि पर दीर्घकालीन ऋण सामान्य ब्याज दर पर उपलब्ध करवाता है, जबकि अन्य बैंकों की ऋण योजनाएं चक्रवृद्धि ब्याज दर पर आधारित हैं।

डेरी क्षेत्र में ऋण के 150 लोगों ने दिखाया रूझान द

सोनीपत केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के स्टाल पर 150 लोगों को डेयरी आधारित योजनाओं पर ऋण की जानकारी दी गई। इसमें 205 महिला स्वयं सहायता समूहों को वीरवार को भी 4 करोड़ 16 लाख रूपए के ऋण चेक वितरित किए गए थे। इसमें 2 भैसों पर बिना सिक्योरिटी के 1 लाख 60 हजार रूपए का ऋण देना भी शामिल है।

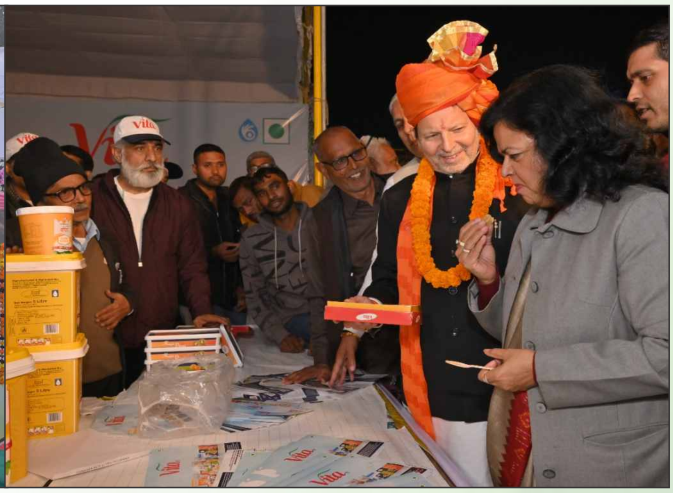

सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित करते सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा

शुगर मिल के 49वें पिराई सत्र की शुरुआत, 50 लाख क्विंटल पिराई का लक्ष्य
गन्ना किसानों को समय पर होगा भुगतान : डॉ. अरविंद शर्मा

करनाल, 19 नवम्बर :– हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने आज यहां शुगर मिल के 49वें पिराई सत्र की शुरुआत की। हवन–यज्ञ के बाद मंत्री ने मशीन में पिराई के लिए गन्ना डाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को मिल में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जायेगी और समय पर भुगतान किया जायेगा।

डॉ. अरविंद शर्मा ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार किसानों को देश में गन्ने का सर्वाधिक भाव दे रही है। उन्होंने बताया कि जिला के 232 गांवों में गन्ने की पैदावार की जा रही है। चीनी मिल इस समय मुनाफे में है। किसानों और मिल प्रशासन की मेहनत की बदौलत मिल को तीन बार पुरस्कार मिल चुका है। इसके लिए उन्होंने किसानों व मिल प्रबंधन को बधाई दी और कहा कि मिल ज्यादा से ज्यादा उन्नति करें। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिये हर वर्ग को भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। भाजपा विश्व की सबसे बडी पार्टी है और मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर प्रदेश की जनता ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिये प्रयासरत हैं। सरकार ने हाल ही में 26 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिये हैं। आने वाले समय में महाराष्ट्र व झारखंड में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार प्रदूषण को लेकर गंभीर है इसके लिए सरकार ने जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक किया ताकि प्रदूषण को कम किया जा सकें।

उन्होंने कहा कि सरकार ने खर्ची–पर्ची सिस्टम को खत्म करके मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। आने वाले समय में दो लाख युवाओं का नौकरियां दी जायेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 33 हजार पंजीकृत समितियां है जिनसे 55 लाख लोग जुड़े हैं। सरकार हर वर्ग की भलाई के लिये वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि मिल तकनीकी दक्षता के मामले में बेहतर परिणाम दे रही है। जिला का किसान काफी मेहनती है।

हरियाणा शुगरफेड के अध्यक्ष धर्मबीर डागर ने किसानों से अपील की कि से मिल में साफ गन्ना लायें ताकि रिकवरी अच्छी हो सके। मिल ने पिछले सत्र में 49.34 लाख गन्ने की पिराई करके 4.90 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया था और मिल की रिकवरी 9.95 प्रतिशत रही थी। इस साल पिराई का लक्ष्य 50 लाख क्विंटल और रिकवरी 10.01 प्रतिशत रखा गया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टोकन से किसानों को समय की बचत हुई है।

इस साल मिल एरिया में गन्ने की बिजाई 22658 एकड़ में की गई है जिसमें से 71 प्रतिशत अगेती और 29 प्रतिशत मध्यम किस्म का गन्ना है। मिल अब तक गन्ना रिकवरी व विकास के लिये 21 बार इनाम प्राप्त कर चुकी है।

इस मौके पर तीन किसानों–कृष्ण खिराजपुर, नेत्रपाल दिलवाड़ा और सोहनलाल चोरपुरा को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। इससे पहले मिल में पहुंचने पर एमडी हितेंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। एमडी ने मिल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। राजपाल लाठर द्वारा मुख्य अतिथि और आए हुए किसानों का धन्यवाद किया।

इस मौके पर केन मैनेजर रोहताश लाठर, मुख्य अभियंता भजन लाल, सुरेन्द्र शर्मा बड़ोता, किशोर नागपाल,इलम सिंह, देवेंद्र शर्मा एडवोकेट, सरदार इंद्रपाल सिंह, देवेंद्र गौतम, प्रकाश नरवाल, इंद्रपाल, ओमपाल, गुरूपाल, सुभाष, सुशील, संदीप आदि मौजूद रहे।

हैफेड शुगर मिल के 17 वें पिराई सत्र की शुरुआत, 24.50 लाख क्विंटल पिराई का लक्ष्य

असंध/करनाल 3 दिसम्बर : हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने मंगलवार को हैफेड शुगर मिल के 17वें पिराई सत्र की बटन दबाकर विधिवत रूप से शुरुआत की। हवन–यज्ञ के बाद मंत्री ने मशीन में पिराई के लिए गन्ना डाला। इस मौके पर असंध के विधायक योगेन्द्र राणा, प्रबन्ध निदेशक हैफेड पंचकूला मुकुल कुमार, महा प्रबंधक विजय सिंह, सी.जी.एम. हैफेड पंचकूला रजनीश शर्मा, जी.एम. हैफेड जोगेन्द्र सिंह व डीजीएम राकेश कुमार मौजूद रहे।

इस अवसर पर डॉ. अरविंद शर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि गन्ना किसानों को मिल में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और उनकी पेमेंट का समय पर भुगतान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षो में मिल ने राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी दक्षता और वित्तीय प्रबंधन में कई पुरस्कार प्राप्त करके क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने किसानों व मिल प्रबंधन को बधाई दी और कहा कि मिल ज्यादा से ज्यादा उन्नति करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को देश में गन्ने का सर्वाधिक भाव दे रही है। आगामी गन्ना सीजन 2025–26 के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए मिल द्वारा गन्ना विकास योजना तैयार की गई है, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपये ब्याज मुक्त ऋण व लगभग 66 लाख रुपये अनुदान देने का प्रस्ताव रखा गया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिये प्रयासरत हैं। नौकरियों में पारदर्शिता रखते हुए सरकार ने हाल ही में 25 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिये हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने खर्ची–पर्ची सिस्टम को खत्म करके मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। आने वाले समय में दो लाख युवाओं को नौकरियां दी जायेंगी। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिये हर वर्ग को भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर प्रदेश की जनता ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में

33 हजार पंजीकृत सहकारी समितियां है, जिनसे 55 लाख लोग जुड़े हैं। सरकार हर वर्ग की भलाई के लिए वचनबद्ध है।

इस अवसर पर असंध के विधायक योगेन्द्र राणा ने सबसे पहले किसानों को गन्ना पिराई सत्र के शुभारंभ पर किसानों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि चीनी मिल असंध द्वारा किसानों के प्रोत्साहन के लिए किसानों को विभिन्न सुविधाओं के रूप में जैसे कि ब्याज मुक्त ऋण पर गन्ना बीज, उर्वरक व कीटनाशक उपलब्ध करवाऐ जा रहें हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि असन्ध चीनी मिल के अंतर्गत क्षेत्र में गन्ने की बिजाई का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हैफेड 2024–25 के लिऐ आकर्षक गन्ना विकास योजना तैयार कर रही है। हैफेड द्वारा किसानों को गन्ने की कीमत का भुगतान अति शीघ्र सीधे किसान के खाते में जमा करवाने व किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करवाकर एक मिसाल स्थापित की है।

उन्होंने कहा कि किसानों के खेत में खड़े गन्ने की एक–एक पोरी खरीदी जाएगी और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा खेतों में गन्ने की पैदावार बढ़ाए। किसान यदि अपने खेतों में फसल बदल बदल कर बोता है तो इससे कृषि भूमि की उपजाऊ शक्ति बढने के साथ–साथ आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी व कर्मचारी सहित सभी वर्गो का समान रूप से विकास करवाया है।

प्रबन्ध निदेशक हैफेड पंचकूला मुकुल कुमार (भा0प्र0से0) ने कहा कि शुगर मिल द्वारा किसानों बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। किसानों को हैफेड चीनी मिल, असंध द्वारा पूरे देश में सबसे पहले 72 घंटों मे गन्ने की पेमेंट का भुगतान किया जा रहा है। चीनी मिल में गन्ना इकाई में अधिक पारदर्शिता लाने के लिये तौल काटों पर स्वचालित काटें लगाए गए हैं व ट्रालियों व ट्रैक्टर के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कैमरे भी लगाए गये हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की सुविधा के लिये उन्हें गन्ना किसान मोबाइल ऐप प्रदान की गई है, जिसमे किसान अपने घर से अपने गन्ने संबंधित रिकॉर्ड चेक कर सकते है व किसानों को मोबाइल संदेश द्वारा भी उनकी गन्ना सर्वे, गन्ना पेमेन्ट व पर्ची ब्यौरा भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए नई तकनीक द्वारा किसानों की गन्ना ट्राली का टोकन किसान खुद अपने घर पर ही मोबाईल द्वारा लगा पाएगा जिससे समय की काफी बचत होगी ।

महाप्रबंधक, हैफेड चीनी मिल असंध ने बताया कि हैफेड चीनी मिल में वर्ष 2008–09 में केवल 1.17 लाख क्विंटल गन्ना पिराई किया था, जो किसान भाईयों के सहयोग से मिल ने पिछले वर्ष 21.88 लाख क्विंटल गन्ना पिराई करके 1.71 लाख क्विंटल चीनी बनाई है, हैफेड शुगर मिल, असंध किसानों की गन्ना पेमेंट का भुगतान करने मे प्रदेश में सबसे आगे है तथा पिछले वर्ष किसानों को लगभग 84 करोड़ गन्ने का भुगतान समय पर किया व गत वर्षो का कोई भी बकाया नहीं है। पिराई सत्र 2024–25 के लिए मिल द्वारा गन्ना विकास योजना पर लगभग 92 लाख रु. किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया गया और 4.31 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में खर्च किये गए। इस वर्ष 2024–25 के लिए गन्ना पिराई का लक्ष्य 24. 50 लाख क्विंटल व रिकवरी का लक्ष्य 9.50 प्रतिशत रखा गया है एवं 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके हरियाणा ग्रिड (उत्तर हरियाणा बिजली निगम) को अनुमानित 24 लाख युनिट बिजली का निर्यात किया जाऐगा। महाप्रबंधक हैफेड चीनी मिल असंध ने किसानों से पूर्ण सहयोग की कामना की तथा ताजा व साफ गन्ना बिना गोला–पत्ती के अपनी पर्ची तिथि के अनुसार मिल में लाने के लिए कहा।

कार्यक्रम में मिल प्रशासन द्वारा हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, असंध विधायक योगेन्द्र राणा, हैफेड के प्रबंधक निदेशक मुकुल कुमार व सीजीएम रजनीश शर्मा को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर जगदेव पाढा, सज्जन अत्री, अमित राणा, रामअवतार जिंदल, बृजलाल टक्कर, मा० नाथी राम, विनय अरडाना, कवंरपाल सालवन, नरेश, अजय, रणदीप, रविदत्त कौशिक अरडाना, रामनिवास जलमाना, विनोद कौशिक, रामफल शर्मा फफडाना, एडवोकेट गुरमीत सिंह सहित काफी संख्या में गन्ना किसान मौजूद रहे।

बॉक्सः–पिराई सत्र में सबसे पहले गन्ना लाने वाले इन किसानों को किया गया सम्मानित।

पिराई सत्र के शुभारंभ अवसर पर सबसे पहले गन्ना लाने वाले किसानों को भी सम्मानित किया गया। इनमें फफड़ाना के दलबीर सिंह, अमरजीत सिंह व रोहित कुमार, अदियाणा के धर्मबीर सिंह, गगसीना के बारू राम, पाढ़ा के तेजबीर शामिल हैं।

हरियाणा में हुआ 710 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण

चंडीगढ़, 18 दिसंबर :–हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने प्रदेश में 710 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस कदम से न केवल इन समितियों की दक्षता में सुधार होगा, बल्कि भ्रष्टाचार से निपटने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने डिजिटल फ्रेमवर्क में निर्बाध बदलाव सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का भी आह्वान किया।

मुख्य सचिव आज यहां राज्य सहकारी विकास समितियों (एस.सी.डी.सी.) की तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में बताया गया कि पैक्स / पी.सी.सी.एस. प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को कवर करती हैं। इसके अलावा, राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के साथ–साथ बहुउद्देशीय पैक्स के गठन के लिए एक संयुक्त कार्य समिति का गठन भी किया गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश में सभी पैक्स / पी.सी.सी.एस. द्वारा उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने और गतिविधियों में विविधता लाने के लिए नए मॉडल उप–नियमों को अपनाया गया है, ताकि वे गांव स्तर पर जीवंत आर्थिक इकाई बन सकें।

केंद्र सरकार की एक पायलट परियोजना के तहत, राज्य के पैक्स नए गोदामों के निर्माण पर भी काम कर रहे हैं। पैक्स लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) सेवाएं भी प्रदान करेंगे। राज्य में 202 पैक्स द्वारा सी.एस.सी. सेवाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। चार पैक्स–बास, मतलौडा, नारनौंद और हथीरा ने जन औषधि केंद्रों में दवाओं की बिक्री शुरू कर दी है। इसके अलावा, 742 पैक्स ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में काम करना शुरू कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि बहु–राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अम्ब्रेला संगठन के रूप में एक नया राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड स्थापित किया गया है। इस सोसायटी के माध्यम से किसानों के उत्पादों के निर्यात में सुविधा होगी तथा किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा। प्रदेश में 420 समितियों को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की सदस्यता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, 347 समितियों को राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड का सदस्य बनाया गया है, जिसे बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। यह संगठन प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के लिए काम करेगा।

इसके अलावा, 499 समितियों को एक नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता प्रदान की गई है, जिसे एक ही ब्रांड नाम के तहत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में स्थापित किया गया है।

मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग को सहकारी समूह आवास समितियों के सदस्यों को पेश आने वाली समस्याओं की पहचान करने के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाने के लिए भी कहा। यह समिति उनकी शिकायतों के समाधान के लिए अपनी सिफारिशें देगी।

दि हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लि. (हरको बैंक) चण्डीगढ़

आज दिनांक 19.11.2024 को पंचकूला के पी.डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाउस, सैक्टर–1 पंचकूला में सहाकरिता सप्ताह के अंतर्गत "सहकारी उद्यमों के परिवर्तन" कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर हरको बैंक के चेयरमैन श्री हुकम सिंह भाटी ने कहा कि इस बैंक का मुख्य उद्देश्य सहकारिता की भावना को बढ़ावा देने के साथ–साथ प्रदेश के लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, उन्होंने बताया कि हरको बैंक ने खरीफ फसल–2024 के दौरान किसानों को मु0. 6081.02 करोड़ रूपये के ऋण उपलब्ध करवाए गए तथा रबी फसल 2024–25 के दौरान मु0.7795.27 करोड़ रूपये के फसली ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध अक्तूबर–2025 तक मु0.505.00 करोड़ रूपये के फसली ऋण वितरित किये गये हैं, उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सहकारी बैंकों को अपने ऋण वितरण करने में वर्गीकरण की आवश्यकता है ।

इस अवसर पर डॉ. प्रफुल्ल रंजन प्रबंध निदेशक/सी. ई.ओ. ने अपने सम्बोधन में कहा कि हरको बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को त्वरित सेवा देने के उद्देश्य के दृष्टिगत कोर बैंकिंग प्रणाली (CBS), EKYC & CKYC, RTGS/NEFT, SMS Alert] ATM, Micro ATM कार्ड सुविधा, मोबाईल वैन, मोबाईल बैंकिंग, IMPS, UPI (Paytm, Phonepe, व GPay) & भारत QR Code for merchants A/c holders, व ऐप्स पर UPI की सुविधा अपने ग्राहकों को देनी प्रारम्भ कर दी गई है और हरको बैंक

शीघ्र ही चण्डीगढ़ व पंचकूला में रूपये डेबिट प्लेटिनम कार्ड व जमा व निकासी ए.टी.एम. मशीन के साथ–साथ ठठ्है का शीघ्र कियान्वयन करने जा रहा है। इसके अतिरिक्त हरको बैंक अपने ऋणी सदस्यों को ऋण के इंश्योरेंस की सुविधा भी जल्द प्रदान करने जा रहा है ।

इस अवसर पर हरको बैंक के महाप्रबंधक श्री कुलदीप कौशिक, श्री अशोक कुमार वर्मा व उप–महाप्रबंधक श्री रमेश पुनिया अन्य अधिकारी व पंचकूला जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबंधक श्री संजीव सिंह व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

शाहबाद चीनी मिल एवं लेबर फेडरेशन द्वारा सहकारी सप्ताह मनाया गया

71वां राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह जो कि हरियाणा में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया गया, इसी कड़ी में 16 नवंबर को शाहाबाद चीनी मिल व लेबर फेडरेशन पंचकूला द्वारा चीनी मिल के इथेनाल प्लांट मे एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाहाबाद चीनी मील से श्री विनोद कनोजिया द्वारा मंच संचालन किया गया। इस अवसर पर चीनी मिल शाहाबाद के एमडी श्री वीरेन्द्र चौधरी जी व लेबर फैड के एमडी श्री वीरेन्द्र कुमार दहिया जी ने उपस्थिति दी व श्रीमती नायब कौर डायरेक्टर चीनी मिल शाहाबाद चीफ गेस्ट रूप में शिरकत की। अपने विचार रखते हुए लेबर फेडरेशन पंचकूला से श्री अमन धीमान एसडीओ व चीनी मील से एस.एस.एम श्री राजीव धीमान भी मौजूद रहे। इनके अलावा चीनी मिल के सभी डायरेक्टर, कुरुक्षेत्र लेबर फेडरेशन के चेयरमैन श्री रामकुमार, वाइस चेयरमैन श्री नरेंद्र घराडसी, लेबर फेड से श्री सुरजीत, लेबर फेड से श्री श्याम लाल सहायक तथा अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। सहकार को आगे बढ़ाने के इस अवसर पर कहीं सो लोग इकट्ठा हुए और उन्हें सहकार सहकारिता के बारे में बताया गया। लेबर फेडरेशन से आए एसडीओ अमन धीमान द्वारा बताया गया कि 50 लाख तक के कार्य समितियों के लिए आरक्षित हैं और धरोहर राशि में भी समितियों के लिए छूट दी गई है। श्रीमती नायब कौर जी ने भी चीनी मिल को लेकर सभी लोगो को अच्छे सुझाव दिये व बताया कि सभी सदस्य एक जुट होके काम करेगे और चीनी मिल को और फायदे की तरफ लेके जाया जाएगा। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने आए हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर सभी सदस्यों व सहकारिता से जुडे आए अन्य लोगो ने चाय–पानी व लंच किया और आपस मे मिल कर काम करने का भरोसा दिलाया।

स्वदेशी अपनाओ, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ

-योगेश शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, हाउसफैड
मो. 9467523666

मैं आप सभी से एक ऐसा विषय साझा कर रहा हूँ जो हमारे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, हमारे भविष्य, और हमारी आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल कल से जुड़ा हुआ है। यह विषय है दृ स्वदेशी अपनाओ, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ।

हमारा देश, भारत, एक महान परंपरा, संस्कृति, और असीमित संभावनाओं से भरा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं, तो हम न केवल अपनी मेहनत की कमाई को विदेशों में भेजते हैं, बल्कि अपने ही देश के कारीगरों, किसानों और उद्यमियों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं?

जब भी हम विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं, तो हम उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, जबकि हमारे देश के उद्योग संघर्ष कर रहे होते हैं। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने देश के कारीगरों, किसानों, और स्थानीय उद्योगों का समर्थन करें? क्या यह गर्व की बात नहीं होगी कि जो भी चीज हम इस्तेमाल करें, वह श्मेड इल इंडियाश हो?

स्वदेशी वस्तुएं खरीदने के 5 फायदे:

1. रोजगार के अवसररू जब हम स्वदेशी उत्पाद खरीदते हैं, तो हम देश के करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं।
2. स्थानीय उद्योग का विकासरू यह कदम हमारे छोटे और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त होती है।
3. गांव और कारीगरों का सशक्तिकरणरू गांवों में बने हस्तशिल्प, खादी, और अन्य उत्पाद खरीदकर हम ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
4. आत्मनिर्भर भारतरू जब हम स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करेंगे, तो भारत को वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी।
5. राष्ट्रीय गवर्रू हर स्वदेशी वस्तु का उपयोग हमें अपने देश पर गर्व महसूस कराता है।

महात्मा गांधी ने भी हमें स्वदेशी का मार्ग दिखाया था। उनके नेतृत्व में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन ने न केवल भारत को आजादी दिलाने में मदद की, बल्कि यह भी सिखाया कि आत्मनिर्भरता ही असली स्वतंत्रता है।

आज हमें एक नई क्रांति की जरूरत है दृ आर्थिक स्वतंत्रता की क्रांति। हमें यह प्रण लेना होगा कि हम अपने हर छोटे–बड़े काम में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देंगे। चाहे वह कपड़े हों, खिलौने हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों, या रोजमर्रा की जरूरत की चीजें दृ हमें भारतीय उत्पादों को चुनना है।

यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक आंदोलन है।

जब हम स्वदेशी उत्पादों को अपनाएंगे, तो हम भारत को विश्व शक्ति बनाने में योगदान देंगे। हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह एक भावनात्मक और राष्ट्रीय कर्तव्य है।

आइए, हम सब मिलकर यह शपथ लें:

हम भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देंगे।

हर भारतीय किसान, कारीगर, और उद्यमी का समर्थन करेंगे।

विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे।

जय स्वदेशी, जय भारत!

हैफेड किसानों व उपभोक्ताओं की सेवा में

हैफेड हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी प्रसंघ है। यह 1 नवंबर, 1966 को हरियाणा के अलग राज्य के रूप में गठन के साथ ही अस्तित्व में आया था। तब से यह हरियाणा के किसानों के साथ–साथ भारत और विदेशों में उपभोक्ताओं की सेवा करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

हैफेड के उद्देश्य हैं:

- कृषि उपज एवं संबंधित उत्पादों की खरीद, विपणन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था करना।
- उर्वरक, बीज और कृषि रसायनों जैसे कृषि इनपुट की आपूर्ति की व्यवस्था करना।

संबंधित सहकारी समितियों के कामकाज को सुविधा जनक बनाना।

हैफेड की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां हैं:

- कृषि इनपुट की व्यवस्था और वितरण • खाद्यान्न की खरीद
- भंडारण • कृषि प्रसंस्करण • उपभोक्ता उत्पादों का विपणन/निर्यात

अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए, हैफेड के पास निम्नलिखित बुनियादी ढांचा है:

- वेयरहाउसिंग/भंडारण क्षमता (गोदाम): 23.39 लाख मीट्रिक टन
- भंडारण क्षमता (खुले प्लिंथ): 6.68 लाख मीट्रिक टन
- पी.ई.जी भंडारण क्षमता: 16.73 लाख मीट्रिक टन
- 7 वर्षीय निजी गोदाम: 3.50 लाख मीट्रिक टन
- पशु आहार संयंत्र: 2 (रोहतक और सकताखेड़ा)
- कीटनाशक संयंत्र: 1 (तरावड़ी)
- सरसों के तेल के संयंत्र: 2 (रेवाड़ी और नारनौल)
- चीनी मिल: 1 (असंध)
- हल्दी का संयंत्र: 1 (रादौर)
- बीज प्रसंस्करण संयंत्र: 1 (गनौर)
- आटा चक्की: 1 (तरावड़ी)
- चावल मिलें: 11
- वाणिज्यिक गोदाम: 3 (मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव)

वर्तमान में, राज्य में हैफेड की 69 कार्यकारी सदस्य सहकारी विपणन समितियां हैं, जो हैफेड की शेयरधारक भी हैं। खाद्यान्नों की खरीद और कृषि इनपुट आदि का वितरण सदस्य सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से किया जाता है

- **खाद्यान्न की खरीद :** रबी 2024–25 हैफेड ने रबी 2024 सीजन के दौरान 35.37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जो राज्य की सभी खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदे गए कुल गेहूं का लगभग 49.46% है। हैफेड द्वारा रबी 2024 सीजन के दौरान 6.92 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है, और राज्य के सूरजमुखी के बीज उत्पादकों को समर्थन देने के उद्देश्य से, हैफेड ने वर्ष 2024–25 के दौरान लगभग 38,903.29 मीट्रिक टन सूरजमुखी के बीज भी खरीदे हैं।
- **खरीफ** 2024–25 :हैफेड ने 30.11.2024 तक 2.28 लाख मीट्रिक टन बाजरा, 15.50 लाख मीट्रिक टन धान और 2664.00 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की है।
- **भंडारण:** पिछले कुछ वर्षों में हैफेड ने 23.74 लाख मीट्रिक टन की कवर्ड स्टोरेज क्षमता बनाई है।इसके अलावा, भारत सरकार की कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना के तहत निजी उद्यमियों के माध्यम से 7 साल की गारंटी योजना के तहत 3.50 लाख मीट्रिक टन गोदामों का निर्माण भी करवाया गया है।
- **निर्यात और विपणन :** वर्ष 2021, 2022, 2023 और 2024 के दौरान, हैफेड ने संयुक्त अरब अमीरात और दुबई से लगभग 1198.95 करोड़ रुपये मूल्य के 1,24,570 मीट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात ऑर्डर प्राप्त किए। जिनमें से लगभग 1,06,569 मीट्रिक टन का पहले ही सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है।
- **विपणन** : वर्ष 2024–25 के दौरान, हैफेड ने नवंबर, 2024 तक लगभग 597.88 करोड़ रुपये के उपभोक्ता उत्पाद बेचे हैं।
- **प्रसंस्करण इकाइयाँ :** रादौर में 7.6 करोड़ रुपये की लागत से हैफेड द्वारा हल्दी तेल पैकिंग लाइन के साथ प्रतिदिन 3 मीट्रिक टन हल्दी प्रसंस्करण क्षमता का एक नया आधुनिक हल्दी संयंत्र स्थापित किया गया है। इसमें 2 मीट्रिक टन प्रतिदिन का बहु–मसालों का प्रसंस्करण संयंत्र और 100 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोर भी है।जाटूसाना (रेवाड़ी) में 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाली एक आटा मिल स्थापित की जा रही है, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 13.60 करोड़ रुपये है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम.ओ.एफ.पी.आई), भारत सरकार की मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत हैफेड द्वारा औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आई.एम.टी), रोहतक में 50 एकड़ के क्षेत्र में एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है जिसकी कुल परियोजना लागत 179.75 करोड़ रुपये है। मेगा फूड पार्क योजना का प्राथमिक उद्देश्य खेत से बाजार तक मूल्य श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करना है। अपेक्षित परिणाम किसानों के लिए अधिक प्राप्ति, उच्च गुणवत्ता वाले प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे का निर्माण, अपव्यय में कमी, उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं की क्षमता निर्माण और एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण के साथ–साथ महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन है।

हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड

डेयरी निगम का गठन 1970 में किया गया था जो 31–03–1977 तक सक्रिय रूप से कार्य करता रहा। तत्पश्चात इसका व्यवसाय फेडरेशन द्वारा अपने अधीन कर लिया गया तथा तीन स्तरीय प्रणाली स्थापित की गई। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के दूध उत्पादकों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, दूध की खरीद और प्रसंस्करण कर उसे दूध उत्पादों में बदलना तथा दुग्ध संघों के माध्यम से उसका विपणन करना तथा डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सहायक सहायक गतिविधियां चलाना, जैसे कि दुग्ध उत्पादन में सुधार करना, दुधारू मवेशी और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना।

- हरियाणा में डेयरी सहकारी समितियां तीन स्तरीय प्रणाली पर काम कर रही हैं
- ग्राम स्तर पर गांव के दूध उत्पादक मिलकर गांव की डेयरी सहकारी समितियां बनाते हैं। इस समिति का प्रबंधन खुद उत्पादक करते हैं
- जिला स्तर पर दुग्ध संघ : एक या एक से अधिक जिलों की दुग्ध सहकारी समितियां मिलकर दुग्ध संघ बनाती हैं। इनका प्रबंधन सहकारी समितियों के अध्यक्षों में से चुने गए दुग्ध उत्पादकों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में, छह मिल्क यूनियन हैं – अंबाला, कुरूक्षेत्र, जींद, बल्लभगढ़, रोहतक, सिरसा
- राज्य डेयरी संघः राज्य दुग्ध संघ राज्य स्तर पर एक शीर्ष निकाय है

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना

- इस योजना के तहत राज्य सरकार हर साल अप्रैल से सितंबर के दौरान गाय और भैंस दोनों के दूध के लिए मौजूदा दर के अतिरिक्त 5 रुपये प्रति लीटर की दर से सहकारी दुग्ध समितियों के दूध उत्पादकों के बैंक खाते में सीधे प्रोत्साहन राशि देती है।
- वर्ष 2024–25 के लिए इस योजना को पूरे वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना में एमपीसीएस को दूध की आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों को 01.04.2024 से 30.09.2024 तक 5 रुपए प्रति लीटर तथा 01.10.2024 से 31.03.2025 तक 3 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि दिए जाने को मंजूरी दी गई है। यह प्रोत्साहन राशि दूध खरीद मूल्य के अतिरिक्त दी जाती है।
- इसके अलावा वर्ष 2024–25 के लिए अंत्योदय परिवार के दूध उत्पादकों को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 01–04–2024 से 31.03.2025 तक 10 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2024.25 के दौरान अप्रैल, 2024 से नवम्बर, 2024 माह तक लगभग 46 करोड़ रूपये के प्रोत्साहन दावें राज्य सरकार को भेजे जा चुके हैं। इन प्रोत्साहन दावों में लगभग 70 लाख दावें अन्त्योदय लाभार्थियों के हैं।
- अब तक जुलाई माह तक 20.84 करोड़ की प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है। यह राशि दुग्ध उत्पादकों के बैंक खाते में डाल दी गई है।

छात्रवृत्ति योजना

- यह योजना दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों (एमपीसीएस) के दुग्ध उत्पादकों के बच्चों को कक्षा 10वीं और 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर क्रमशः 2100/– रुपए और 5100/– रुपए की एकमुश्त छात्रवृत्ति देने की है। यह योजना 1 मार्च 2015 से लागू की गई है। इस योजना के तहत 01 मार्च 2015 से 31 अक्टूबर 2024 तक लगभग 6087 दुग्ध उत्पादकों के बच्चों को 220.437 लाख रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई है।

कन्यादान योजना

- दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों (एमपीसीएस) के दुग्ध उत्पादकों की पुत्री के विवाह पर 1,100 रुपए देने की कन्यादान योजना 1 मार्च 2015 से लागू की गई है।
- इस योजना के तहत 01 मार्च 2015 से 31 अक्टूबर 2024 तक लगभग 3092 दुग्ध उत्पादकों को उनकी पुत्री के विवाह पर 33.62 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है।

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर

- सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों के लिए यह योजना 1 मार्च 2015 से लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 से प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के तहत हरियाणा में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों (एमपीसीएस) से जुड़े लगभग 50,000 दुग्ध उत्पादकों में से प्रत्येक का 10 लाख रुपये प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा किया गया है। प्रति सदस्य प्रति वर्ष बीमा की दर 223.88 रुपये है। जिसमें से 56 रुपये दुग्ध उत्पादक सदस्य द्वारा तथा शेष दुग्ध संघ द्वारा वहन किया गया है।
- बीमा कंपनी द्वारा 01.03.2015 से 31.10.2024 तक कुल 79 बीमा दावों (450.00 लाख रुपये) का निपटान किया गया है।

सहकारी चीनी मिल प्रसंघ

हरियाणा सहकारी चीनी मिल प्रसंघ की स्थापना वर्ष 1966 में राज्य में स्थापित सहकारी चीनी मिलों की कार्य कुशलता में सुधार एवं राज्य में नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना करने के उद्देश्य से की गई थी। इस समय हरियाणा में 10 सहकारी चीनी मिलें प्रसंघ के नियन्त्रण के तहत कार्यरत हैं तथा एक अन्य सहकारी चीनी मिल, असंध (2500 टीसीडी) हैफेड द्वारा चलाई जा रही है।

उद्देश्य

- नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना और मौजूदा मिलों का उन्नयन
- भारत सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय संस्थाओं से धन की व्यवस्था
- मौजूदा सहकारी चीनी मिलों को सलाह एवं सहायता प्रदान करना
- गन्ना विकास योजना की तैयारी
- चीनी मिलों के लिए एक समान नीतियों और नियमों का निर्माण
- गतिविधियों का विस्तार जैसे कोजन संयंत्र, इथेनॉल संयंत्र, बायोगैस संयंत्र आदि।

चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, वर्ष 2021–22 में शाहबाद सहकारी चीनी मिल में 99 करोड़ रूपये की लागत से 60 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के **इथेनॉल** प्लांट की स्थापना की गई है तथा पानीपत सहकारी चीनी मिल मे 150.64 करोड़ रूपये की लागत से 90 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का **इथेनॉल** प्लांट लगाने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है

भविष्य में शेष सभी सहकारी चीनी मिलों में भी सामूहिक आधार पर 690 के.एल.पी.डी के एथनॉल प्लांट लगाये जाने प्रस्तावित है व इन परियोजनाओं पर लगभग 1200 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।

सामूहिक आधार पर बायो–सी.एन.जी. यूनिटस स्थापित करने की संभावना भी तलाशी जा रही है।

हरियाणा में गन्ने का लाभप्रद राज्य सुझावित मूल्य।

पिराई सीजन	किस्मानुसार गन्ने की कीमत (रूपये प्रति क्विंटल)	
	अगेती	मध्यम / पछेती
2024–25	400	393

हरियाणा राज्य सहकारी शीर्ष बैंक लि०.(हरको बैंक) व जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

हरियाणा राज्य में हरको बैंक व जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ऋण योजनाएं

राज्य में सहकारी बैंक मुख्यतः कृषि व गैर कृषि दो प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं:–

कृषि ऋण योजनाएं:–

1. अल्पावधि (एस.ए.ओ.) किसान क्रेडिट कार्ड :–1.50 लाख रूपये (संपार्श्विक सुरक्षा के साथ इसे 3.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है), 7% सदस्यों से (केंद्र सरकार द्वारा 3% और राज्य सरकार द्वारा 4% की दर से ब्याज छूट)
2. रिवोल्विंग कैश क्रेडिट सीमा, 7.00 लाख रूपये, 10% से 12% सदस्यों के बीच भिन्न होता है ।
3. अल्पावधि गैर कृषि (ग्रामीण दस्तकारों व छोटे दुकानदारों), 35000 / –रूपये, 10% से 12% सदस्यों के बीच भिन्न होता है ।
4. अल्पावधि उर्वरक (Fertilizer) ऋण, 37,500 / – रूपये, 7% सदस्यों से
5. चीनी मिलों को नकद उधार, 1142.00 करोड़ रूपये,11% चीनी मिलों से
6. दीर्घावधि ऋण चीनी मिलों को, 243.92 करोड़ रूपये, 10.10% चीनी मिलों से
7. खाद्य प्रसंस्करण, बाग, लघु सिंचाई गतिविधियाँ कृषि क्षेत्र आदि से संबंधित, 35,000 / – रूपये व अपने स्तर से बढ़ाया गया, 12% और समय–समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

गैर कृषि ऋण योजनाएँ:–

1. सरकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत ऋण, 15.00 लाख रूपये, 10% से 10.75% सिबल स्कोर के आधार पर 7 वर्ष की अवधि के लिए, 0.10% रियायत महिला के लिए
2. शहरी क्षेत्र में आवास ऋण, 75.00 लाख रूपये, 8.40: सिबल स्कोर के आधार, 20 वर्ष तक, 0.10: रियायत महिला के लिए
3. शिक्षा ऋण (सरस्वती), 40.00 लाख रूपये, 10 से 12%, 15 वर्ष तक, 1% रियायत महिला के लिए
4. कार ऋण, 40.00 लाख रूपये, 8.70 से 9.45% वार्षिक, 7 वर्ष तक, 0.10% रियायत महिला के लिए
5. प्रापर्टी के विरूद्ध ऋण, 60.00 लाख रूपये, 10% अधिकतम 10 वर्ष
6. पेंशनर के लिए ऋण, 10.00 लाख रूपये, 11.25 से 12%
7. ई–रिक्शा, 1.50 लाख रूपये, 36 माह
8. उपभोक्ता ऋण, 2.00 लाख रूपये, 12%
9. स्वर्ण ऋण, 10.00 लाख रूपये या मूल्य का 60 प्रतिशत, 8.90%
10. शिक्षा ऋण (कौशल),1.50 लाख रूपये, 9 से 12% 7 वर्ष के लिए

वर्ष 2024–25 के दौरान हरको बैंक द्वारा लागू की गई जमा योजनाएं:–

1. हमारी बिटिया, 7.25%, 5 वर्ष के लिए,10.00 लाख रूपये तक
2. हमारा लाडला, 7.10%, 5 वर्ष के लिए, 10.00 लाख रूपये तक
3. आज़ादी का महोत्सव, 7.10%, 399 दिनों के लिए

- **महिला सहकारी समितियों को सब्सिडी:–** केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के 5.00 लाख रूपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक सोसायटी को 20 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 1.00 लाख रूपये अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- **सब्जी एवं फल उत्पादक सहकारी समितियों को सब्सिडी:–** केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के 5.00 लाख रूपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक सोसायटी को 20 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 1.00 लाख रूपये अनुदान प्रदान किया जाएगा।

कम्पूयटरीकरण:–

हरको बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को त्वरित सेवा देने के उद्देश्य के दृष्टिगत कोर बैंकिंग प्रणाली (CBS), EKYC & CKYC, RTGS/NEFT, SMS Alert ATM, Micro ATM कार्ड सुविधा, मोबाईल वैन, मोबाईल बैंकिंग, IMPS,UPI (Paytm, Phonepe व Gpay) & भारत QR Code for merchants A/c holders, व ऐप्स पर UPI की सुविधा अपने ग्राहकों को देनी प्रारम्भ कर दी गई है।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का योगदान

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014 में "समय पर ऋण अदा करने वाले ऋणियों के लिए ब्याज राहत योजना" लागू की गई जिसकी अवधि 31.03.2024 तक थी। इस योजना के तहत 25.08.2014 से 30.06.2023 तक 101.01 करोड़ रुपये की ब्याज राहत प्रदान की गई है। अब, राज्य सरकार. ने योजना को 31.03.2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ (हरकोफैड)

हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ, लि0 जो हरकोफैड के नाम से विख्यात है, एक नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य के पृथक राज्य बनने के समय पंजाब राज्य सहकारी यूनियन के विभाजन स्वरूप अस्तित्व में आई। यह संस्था विभिन्न सहकारी संस्थाओं तथा राज्य सरकार के बीच मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करती है। हरकोफैड द्वारा अपने सदस्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्मचारियों व सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है सहकारिताओं की गतिविधियों एवं उपलब्धियों का प्रचार भी किया जा रहा है।

गतिविधियाँ :–

संस्था की मुख्य गतिविधियां निम्न प्रकार हैं :–

1. सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण ।
2. प्रचार एवं लोक सम्पर्क ।
3. मुद्रण कार्य।
4. सहकार से सम्बंधित अन्य गतिविधियाँ सरकार के आदेशनुसार।

हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण प्रसंघ लि0, पंचकुला (लेबरफैड)

हरियाणा सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों को दी गई सुविधाएं/रियायतें

- 50 लाख रूपये तक के सभी (कुशल/अकुशल) कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के सर्कल में आई निविदाओं के न्यूनतम रेट अनुसार प्राथमिक श्रम एवं निर्माण सहकारी समितियों के लिए पूर्ण रूप से आरक्षित होंगे।
- उपरोक्त कार्यों के लिए 25000 रूपये या 1 प्रतिशत जो भी कम हो, धरोहर राशि का भुगतान करेंगी तथा 50 लाख रूपये से अधिक के कार्यों के लिए धरोहर राशि ठेकेदारों पर लागू धरोहर राशि का 50 प्रतिशत होगी।
- सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों के लिए निष्पादन सुरक्षा किसी भी मूल्य तक के कार्यों के लिये ठेकेदारों पर लागु निष्पादन सुरक्षा का आधा होगी। जिस समिति के सभी सदस्य महिलाएँ या अनुसूचित जाति से है, उनके लिए निष्पादन सुरक्षा ठेकेदारों पर लागू निष्पादन सुरक्षा का 25 प्रतिशत होगी।
- सरकारी अस्पतालों और शहरी स्थानीय निकायों में सफाई के कार्य उन समितियों के लिए आरक्षित होंगे, जिन समितियों के सभी सदस्य अनुसूचित जाति से है।

सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायताः–

- सरकार समितियों को 80,000 रुपये की शेयर पूंजी, 80,000 रुपये का सरकारी ऋण और 40,000 रुपये की सब्सिडी के रूप में 2.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- सहकारी बैंक उन समितियों को ब्याज अनुदान भी प्रदान करता है जो ऋण को ब्याज सहित समय पर चुका देती हैं।
- सहकारी बैंक निम्नलिखित वित्त सुविधाएं श्रम एवं निर्माण समितियों को प्रदान करता है:–

(क) नकद ऋण सीमा 2.00 लाख रुपये तक।
(ख) 5.00 लाख रुपये तक के लंबित बिलों पर ऋण।
(ग) 20.00 लाख रुपये तक का सुरक्षित ऋण।

दी हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ लि0 पंचकूला

हरियाणा सरकार द्वारा हाउसफैड की समितियों के ऋणी सदस्यों के लिए जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक एक मुश्त कर्ज निपटान योजना स्वीकृत की थी। इस योजना के अतंर्गत 250 ऋणी सदस्यों से 13 करोड़ रूपये की वसूली प्राप्त की तथा इस योजना से लाभार्थियों को लगभग 9 करोड़ रूपये जुर्माना ब्याज माफी की राहत दी गई।

हरको बैंक मुख्यालय में सौलर पैनल का उद्घाटन व लिफ्टों का शिला न्यास बारे प्रैस विज्ञप्ति

आज दिनांक 24.12.2024 को हरको बैंक के माननीय चेयरमैन श्री हुकम सिंह भाटी व प्रबंध निदेशक / सी.ई.ओ. डॉ. प्रफुल्ल रंजन द्वारा चण्डीगढ़ प्रशासन के दिशा–निर्देशों की अनुपालना करते हुये बैंक में 30 किलोवाट के सौलर पैनल का भवन की छत पर उद्घाटन किया गया है, इस अवसर पर डॉ. रंजन ने बताया कि इस परियोजना पर लगभग 16.50 लाख रूपये की लागत आई है और इसकी उर्जा उत्पादन क्षमता 120 युनिट प्रतिदिन है, इससे बैंक को प्रतिवर्ष लगभग मु0.3. 50 लाख रूपये की बिजली की बचत होगी तथा प्र्यावरण के दृष्टिगत बैंक द्वारा यह उत्तम पहल की गई है । उन्होंने यह भी बताया कि हरको बैंक के मुख्यालय व स्टाफ कलौनी सैक्टर–20 पंचकूला में जो 12 लिफ्टे लगी हुई हैं, जोकि काफी पुरानी हो चुकी थी, उनके स्थान पर नई लिफ्टे लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि बैंक मुख्यालय भवन, चण्डीगढ़ व कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र पंचकूला के रेनोवेशन के कार्य हेतू बैंक द्वारा हरियाणा वेयरहाउस कारपोरेशन से करार किया गया था, जिसका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा भवन को उत्कृष्ठ रूप से सुसज्जित किया जायेगा।

इस अवसर पर डॉ. रंजन ने हरको बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों को बैंक के व्यावसाय व लाभप्रदत्ता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और सभी का आहवान किया कि वे सभी बैंक की प्रगति में अपना शत–प्रतिशत योगदान दें ।

नैनो उर्वरक जागरूकता अभियान-किसान सभा, गांव बलियाला - टोहाना

टोहाना : आज दिनांक 19 दिसंबर 2024 को गाँव बलियाला में इफको टोहाना द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया । कार्यक्रम में श्री सुशील कुमार (क्षेत्रीय अधिकारी इफको टोहाना) ने इफको के नवीनतम उत्पाद नैनो यूरिया प्लस एवं नैनो डीएपी के उपयोग हेतु जानकारी साँझा की । उन्होंने बताया कि साधारण यूरिया की दक्षता मात्र 30% रहती है तथा बाकि यूरिया मिट्टी, जल एवं वायु प्रदूषण का कारण बनती है इसके मुकाबले नैनो यूरिया प्लस की दक्षता 90% है तथा वातावरण में किसी प्रकार प्रदूषण नहीं करती । नैनो यूरिया प्लस में नत्रजन की मात्रा को बढ़ा कर 20% किया गया है जो साधारण यूरिया खाद के अपेक्षाकृत अधिक कारगर है । किसानों को ड्रोन के माध्यम से फसलों पर नैनो उर्वरकों

के छिड़काव के प्रति जागरूक किया गया । इफको द्वारा दो ग्रामीण युवाओं को ड्रोन उपलब्ध करवाया गया है जो टोहाना तथा भूना क्षेत्र के गावों में फसलों पर नैनो उर्वरकों के छिड़काव का कार्य करेंगे ।

हरकोफैड की ओर से आयोजित लेख व ड्राइंग प्रतियोगिता में 9 स्कूलों के विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा
लेख में मुस्कान और ड्राइंग में ओम प्रकाश रहे अव्वल

पंचकूला, हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ (हरकोफैड) की ओर से पीएमश्री राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय सेक्टर–15 पंचकूला में लेख, ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इनमें जिले के नौ राजकीय स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया।हरकोफेड की शिक्षा अनुदेशिका निधि मलिक ने बताया कि लेख प्रतियोगिता महिला सशक्तीकरण और युवा उत्थान में सहकारिता की भूमिका पर आधारित थी। पेंटिंग और ड्राइंगलेख प्रतियोगिता के विजेता लेख प्रतियोगिता में सेक्टर–15 स्कूल की छात्रा मुस्कान ने प्रथम, संकेतड़ी स्कूल की छात्रा शिवानी ने दूसरा स्थान, नानपुर स्कूल की छात्रा शान्या ने तीसरा स्थान और सेटर–6 की छात्रा गरिमा और रामगढ़ स्कूल की छात्रा सृष्टि गिरी ने सांत्वना पुरस्कार हासिल किया।प्रतियोगिता समुदाय के प्रति निष्ठा विषय पर केंद्रित थी।इसमें राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोट, कालका, नानकपुर, पिंजौर, बिटना, सकेतड़ी, रामगढ़, सेक्टर–6 और सेक्टर–15 के करीब 50 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। लेख प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका केदार नाथ ने निभाई। पेंटिंग व ड्राइंग प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका प्रोफेसर अनीता और सेवानिवृत्त प्राध्यापक मिनी पुरी रही।ड्राइंग के विजेता ड्राइंग प्रतियोगिता में पिंजौर स्कूल के छात्र ओम प्रकाश ने प्रथम, कोट स्कूल की छात्रा समता ने दूसरा, बिटना स्कूल की छात्रा मुस्कान ने तीसरा और पिंजौर स्कूल की छात्रा आयशा व कालका स्कूल की छात्रा आकृति 'ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया।

प्राथमिक सोसायटी का उद्देश्य किसानों को बढ़ावा देना व उन्हें विकसित करना : ऋषिपाल

कौल, 31 दिसम्बर (बलवान) द कौल प्राइमरी कृषि सहकारी समिति लिमिटेड में आज हरियाणा राज्य सहकारिता विकास प्रसंग लिमिटेड हरकोफैड पंचकूला की ओर से किसान प्रशिक्षण में करीब 50 से अधिक किसानों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे हरकोफैड के ए. सी.ओ. ऋषिपाल ने सहकारी समिति की स्कीमों के बारे में किसानों को विस्तारपूर्वक बताते हुए कहा कि प्राथमिक सोसायटी उद्देश्य किसानों को बढ़ावा देना और उन्हें विकसित करना है।

इसके साथ ही सेवा या व्यवसाय संचालन (जैसे बुनियादी ढांचे का विकास, खाद्यान्न की खरीद, उचित मूल्य की दुकान या कोई सरकारी योजना, डीलरशिप, एजैंसी, एल.पी.जी., पैट्रोल, डीजल आदि) की सुविधाओं व आय में वृद्धि हो सके।

उन्होंने कहा कि हरकोफैड का लक्ष्य हमेशा किसान–मजदूरों के उद्देश्यों व सेवाओं से संबंधित विस्तार गतिविधियों का विकास करना है। कार्यक्रम के अंत में द कौल प्राइमरी कृषि सहकारी समिति लिमिटेड के प्रबंधक राजीव साकरा ने सभी का आभार व्यक्त किया।

वहीं हरकोफैड से ज्योति देवी ने सभी किसानों एवं वक्ताओं का स्वागत किया एवं सहकारी समिति के बारे में बताया। इस मौके पर हैड क्लर्क राज कुमार, राजपाल, जगदीश, पूर्व सरपंच ओमप्रकाश खेड़ी साकरा, नरेश शर्मा, प्रिंस, संजय कुमार, सतपाल, शिव कुमार, दर्शन सिंह व अन्य उपस्थित रहे।

फसल को लेकर किसानों को किया जागरूक

काछवा : दिनांक 31 दिसम्बर 2024 को दी प्राइमरी कृषि सरकारी समिति लिमिटेड काछवा में हरियाणा राज्य सहकारी विकास लिमिटेड पंचकूला की ओर से किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में करीब 50 से अधिक किसानों ने भाग लिया सरकारी बैंक के प्रबंधक ने लोन की स्कीमों के बारे में किसानों को अवगत कराया। फसल बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्राकृतिक खेती के बारे में प्रगतिशील किसान बजाज ने किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हरकोफैड से श्रीमती ज्योति देवी ने सी.एम. पैक्स व मल्टीपरपज सोसायटी के बारे में सभी किसानों को विस्तृत जानकारी दे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वक्ताओं और किसानों का धन्यवाद किया।

ROLE OF COOPERATIVES IN 'VIKSIT BHARAT'

Viksit Bharat (Developed India) is a vision and goal for India to achieve comprehensive across multiple sectors, transforming it into a developed nation. This term is often used in Government policy discussions, political rhetoric and national development strategies. The vision of "Viksit Bharat" includes objectives like high economic growth, technological advancement, social equality, environmental sustainability and enhanced global standing. Besides, "Viksit Bharat" is not only about economic progress but also aims for social justice. Ensuring that marginalized groups, including women, rural populations and minority communities benefit from development is one of the primary goals.

With approximately 25 percent of the world's cooperatives located in India, Cooperative in India are poised to play a pivotal role in India to achieve Viksit Bharat goal of the Modi Government by 2047. Cooperatives have made significant contributions to India's economy, including food security, poverty alleviation, management of natural resources and the environment, sustainable development, and social inclusion. India's strong cooperatives driven by digital including, upholding socio-economic livelihood and financial inclusion have driven structural reforms and opened up the economy for the progressive and developmental agenda of Viksit Bharat.

Meanwhile, "Viksit Bharat" and cooperatives share symbiotic relations, having independence, and fair allocation of resources. In India, the cooperative sector has evolved through green, white and blue revolution and is very crucial for achieving $5trilling economy. Cooperatives are community driven groups established by individuals or small-scale producers (women/farmers/professional) to jointly oversee and run businesses, usually in agriculture, finance, dairy, banking, housing and other industries. Traditionally, these cooperatives enable the local communities, be they rural or urban, to substantially support the goal of an advanced India.

ROLE OF COOPERATIVES IN INDIA'S DEVELOPEMENT AGENDA

Economic Empowerment :

Cooperative offer a forum for individuals, particularly small-scale farmers, artisans and business owners and women to pool their resources and attain mutual advantages. This is especially crucial for attaining financial empowerment in rural and marginalized regions, where cooperatives play a key role in connecting producers with the market. Amul, is one such example, which is the biggest dairy cooperatives can contribute to economic growth demonstrated how cooperatives can contribute to economic growth and enhance the lives of farmers. Amul played a pivotal role in

revolutionizing India's dairy sector and establishing India as one of the leading milk producers globally.

Agriculture and Rural Development :

1. Modernizing agricultural systems is equally essential for the development of ' Viksit Bharat', Cooperatives play a crucial role in rural India ensuring increased productivity and equitable prices for farmers. Cooperative collectives allow, farmers to collectively buy items such as seeds, fertilizers and equipment and to market their crops more effectively, leading to higher incomes ad contributing to rural development. For instance, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), a prominent cooperative, supplies fertilizers and other necessary resources to farmers, making a significant contribution to the agricultural growth of India.

Cooperative institutions are merged and function as PACS and these organizations are now serving as Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras and managing thousands of Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendras, Furthemore, Cooperative societies are repurposed as retail outlets for petrol and diesel and many are now involved in the distribution of LPG cylinders. PACS are also taking on the role of ' Pani Samitis' (water Committees) in numerous villages. In summary, the significance of PACS and credit societies is growing, and their sources of income are expanding as well.

2. Cooperatives are inherently designed to foster fair growth and social integration, making them vital for promoting inclusive development and reducing poverty. They offer marginalized communities, including small scale farmers, women and rural entrepreneurs, a share in economic progress. This inclusivity is crucial for achieving the vision of " Viksit Bharat" where development benefits all strata of society. For instance, organizations like SEWA (self –Employed Women's Association) empower women through microfinance, training, and access o markets, thus enabling them to achieve financial autonomy. The Lajjat Papad's - a women's cooperative success is commendable.

Financial Inclusion and Cooperative in the Banking Sector

Cooperative banks and credit societies in rural and urban areas have revolutionized financial services to communities, where access to formal banking institutions is limited. Cooperatives promote savings, offer credit and provide insurance services, thus promoting financial inclusion, which is vital for economic development. Example: The National Cooperative banks and societies that offer financial assistance to farmers and small businesses.

Cooperative play a significant role in creating employment opportunities, especially rural area, through activities such as farming, agro-processing, handicrafts and small-scale industries, thereby providing jobs for millions and addressing rural unemployment and migration to urban areas. Cooperatives advocate for sustainable and community-driven development models, with a focus on responsible resource management, which includes sustainable farming practices, organic agriculture and renewable energy projects. These efforts are in line with the broader objectives of environmental sustainability in a "Viksit Bharat." For instance, Cooperatives that promote organic farming or focus on renewable energy can contribute to the "Green India" mission.

Government Support for Cooperatives in India

a. In recognition of Cooperatives the Government of India has introduced various policies and institutions to support their growth. This support is aligned with the broader goal of achieving a " Viksit Bharat" .

b. Cooperative Societies Act: The Multi-state Cooperative Societies Act, 2002 facilitates the formation and functioning of cooperatives

across state boundaries enabling them to operate on a larger scale.

c. Ministry of Cooperation: In July 2021, the Government of India created a dedicated Ministry of Cooperation to strengthen of Cooperative movement. This Ministry is responsible for developing movement. This Ministry is responsible for development policies to enhance the role of cooperatives in areas like agriculture, rural development and financial services.

d. National Cooperative Development Corporation (NCDC): The NCDC provides financial and technical support to cooperative in various sectors, including agriculture, fisheries and rural industries. This plays a key role in empowering cooperatives to achieve scale and impact.

e. Digitalization of Cooperatives: As part of the Digital India initiative, the Government is promoting the digitalization of cooperative to improve transparency, governance and efficiency in their operations. This will enable cooperatives to better connect with markets and Government programs, enhancing their contribution to " Viksit Bharat" .

f. Establishment of 200,000 New Multi-Purpose Cooperative Societies: To cover underserved areas over the next five years.

g. White Revolution 2.0: Aiming to increase milk procurement of dairy cooperative by 50 % over the next five years by providing market access to dairy farmers in uncovered areas and increasing the share of dairy cooperative in the organised the share of dairy empower women and tackle malnutrition and other multifaceted issues.

h. Cooperation among Cooperatives: Enhancing collaborative efforts within the sector

i. The Government has empowered Primary Agriculture Credit Societies (PACS) to engage in over 25 different activities by drafting a new model by-law.

Kay challenges faced by cooperatives

Despite their potential, Cooperative face several challenges that need to be addressed to fully realize their contribution to the " Viksit Bharat" vision.

1. Limited Professional Management: Many cooperatives especially in rural areas, lack professional management and technical expertise, which limits their efficiency and capacity to scale.

2. Political Interference: In some cases, cooperatives are subject to political interference, which can compromise their autonomy and effectiveness.

3. Financial Constraints: Access to finance remains a challenge for many small cooperative, as they may not have the collateral or credit history required to obtain loans from formal financial institutions.

4. Awareness and Education: Many cooperative members lack awareness about the benefits of cooperative and the rights and responsibilities of members. Education and capacity-building programs are necessary to empower members effective participate and manage their cooperative.

5. Fragmentation: The cooperative sector in India fragmented, with many Small, localized cooperative operating independently. Greater coordination and collaborating between cooperative could enhance their bargaining power and ability to access Market.

Conclusion

Cooperatives play a crucial role in India's development journey toward a "Viksit Bharat." By empowering rural population promoting inclusive growth and ensuring equitable access to resources, cooperative contribution to reducing poverty and improving livelihoods strengthen the cooperative movement is essential for a "Viksit Bharat".

बापू आज भी प्रासंगिक हैं

बापू विश्व के इतिहास में उन बहुत कम महान व्यक्तियों में से एक है जो विश्व पटल पर हमेशा के लिए अनुपम और अद्वितीय छाप छोड़ कर अमर हो गए हैं। आज भी बापू हमारे बीच प्रासंगिक हैं और सदा रहेंगे। गांधी जी का जीवन बड़ा ही सरल, सादा और कठिन नियमों से बंधा हुआ था। सत्य, अहिंसा तथा नैतिकता के नए अनोखे प्रयोग के आधार पर भारत को अंग्रेजी शासन से आजादी दिलाने में उनका यह उत्कृष्ट उदाहरण विश्व के इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलता।

गांधी जी ने भारतीयों की दयनीय स्थिति और उन पर अंग्रेजी सत्ता के अत्याचारों का मुख्य कारण भारतीय समाज में नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का अभाव माना। जिससे छुटकारा पाने के लिए भारतीय संस्कृति तथा देशज मूल्यों की उपयोगिता को मान्यता देना और अंग्रेजी शासन के मुकाबले के लिए उन्होंने नैतिक शक्ति के रूप में सत्य और अहिंसात्मक तरीकों के प्रयोग को महत्वपूर्ण माना। भेदभाव का मुकाबला करने के लिए उनके पास सत्य की शक्ति थी, अहिंसा पद्धति नैतिक दर्शन और सत्य अहिंसा उनका बल था। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों ने उनके विचारों और दर्शन को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक सर्वोच्च शक्ति ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास हो गया और उन्होंने आजीवन सत्य और अहिंसा के अतिरिक्त किसी अन्य विचार को नहीं स्वीकारा।

सत्य – सत्य के विषय में गांधी जी का स्पष्ट मत है कि सत्य के लिए साधना तथा प्रतिबद्धता मानव के अस्तित्व को न्यायसंगत ठहराता है जो आत्मप्रेम को आत्मत्याग में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि सत्य केवल एक है जो पूरे विश्व पर छाया है। इसलिए सत्य वास्तविक आनंद है। अहिंसा का पालन करते हुए व्यक्ति आत्मशुद्धि कर लेता है तब उसका अंतःकरण सत्य का दर्पण बन जाता है और शुद्ध अंत : करण ही ईश्वर का मंदिर है।

अहिंसा – सत्य और अहिंसा को गांधी जी ने स्वयं में ईश्वरीय रूप बतलाया तथा दोनों को साध्य और साधना माना। अहिंसा मानव और सामाजिक जीवन में प्रेम की पहली अभिव्यक्ति है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि मैंने सत्य की खोज में अहिंसा को प्राप्त किया है। इसलिए की पवित्रता के महत्व पर बापू ने विशेष बल दिया और कहा कि व्यक्ति को विचार, भाषण और तन के साथ मस्तिष्क से भी अहिंसक होना चाहिए।

नैतिक दर्शन – बापू ने व्यक्ति के साथ–साथ सारे समाज को नैतिक बनाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि पृथ्वी का सूक्ष्मतम प्राणी भी ईश्वर का प्रतिरूप होने के कारण तुम्हारे प्यार का अधिकारी है, जो अपने साथ जीवन बिताने वाले मनुष्यों से प्यार करता है, वही ईश्वर से प्रेम करता है।

भेदभाव एवं छुआछूत – गांधी जी ने मनुष्यों द्वारा आपस में भेदभाव को बहुत बड़ा अभिशाप माना है। अहिंसा का सकारात्मक अर्थ पृथ्वी पर सभी प्राणियों से प्रेम है। यह अपना है, यह पराया है, ऐसा संकीर्ण मनोवृति के लोग ही सोच सकते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए सारी पृथ्वी एक कुटुंभ की तरह है। जिसका निर्माण उस समय के प्रमुख उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला ने सन् 1933 से 1939 के बीच में होते हुए भी एक शर्त रख दी कि मंदिर में हरिजनों के प्रवेश पर रोक नहीं होगी। बिड़ला जी गांधी जी की यह शर्त सुन कर अचंभित हो गए, क्योंकि उस दौर में हरिजनों के मंदिरों में प्रवेश पर तरह–तरह के अवरोध खड़े किए जाते थे। परंतु अंत में बिड़ला जी को बापू की शर्त माननी पड़ी। उसके बाद इस भव्य मंदिर का उद्घाटन गांधी जी ने सितंबर, 1939 को अपने कर कमलों द्वारा किया।

अपनी पत्रिका 'यंग इंडिया' में अप्रैल, 1925 में गांधी जी ने लिखा था, 'मंदिरों, कूओं और स्कूलों में जाने पर जाति के आधार पर किसी तरह की रोक गलत है।' इसी कड़ी में उन्होंने 7 नवंबर, 1933 से अगस्त 1934 के बीच छुआछात खत्म करने के लिए देशभर की यात्रा भी की जिसे गांधी जी की ' हरिजन यात्रा या दौरा' के नाम से याद किया जाता है।

उपवास उपचार है – बापू जी के कथानुसार उपवास एक उपचार भी है जो आत्मिक शुद्धि और विश्वास देता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के परिवेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा– 'सत्य के प्रयोग' में उपवास के महत्व का

वर्णन है। उनकी आत्मकथा से उद्बव अंश के अनुसार 'उपवास मात्र शारीरिक शुद्धि की नहीं, बल्कि आत्मिक एवं आध्यात्मिक शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। उनके अनुसार उपवास के लिए मन की पवित्रता, एकाग्रस्ता, समरसता, निःस्वार्थ भाव और धैर्य आवश्यक हैं। गांधी जी सत्याग्रह के संदर्भ में उपवास को अहिंसा का सशक्त माध्यम मानते थे। गांधी जी के अनुसार मात्र अन्न के त्याग को उपवास नहीं कहा जा सकता। उपवास के लिए पर्याप्त मनोबल की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि आत्म चितंन के बगैर उपवास सत्याग्रह संभव नहीं हैं।

स्वच्छता – गांधी जी के स्वाधीनता संग्राम से स्वच्छता, उपवास, सत्याग्रह और स्वास्थ्य संगंधी प्रसंग भी महत्वपूर्ण हैं। दक्षिणी–अफीका में बापू अपने दूसरे प्रवास पर थे तब वहां पर भारतीयों को सफाई पसंद नहीं माना जाता था। बापू ने इसे गलत साबित करने के लिए भारतीयों से अपने स्नानग्रह स्वच्छ रखने की सलाह दी। उन्होंने केवल उपदेश ही नहीं दिया बल्कि खुद घर–घर जाकर सफाई करने लगे। बापू मानते थे कि बाह्य और आंतरिक स्वच्छता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गांधी जी चाहते थे कि देश के सभी लोगों को उनके घर में साफ–सफाई की सुविधाएं यानी शौचालय उपलब्ध हों। वह महिला और पुरूषों के घर से बाहर शौच के लिए जाने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि खुले में शौच करने से वातावरण प्रदूषित होता है और गंदे स्थानों पर शौच करने से संक्रामिक रोगों का खतरा बन जाता है। शौचालयों के संदर्भ में गांधी जी की इच्छा को वर्मामान सरकार ने साकार रूप देकर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पूरी तरह से प्रयासरत है, जिसका विधिवत शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर, 2014 को बापू जी के जन्म दिवस पर नई दिल्ली की हरिजन बस्ती से किया जिसको देशभर में जनता का अपार सहयोग मिल रा है।

यदि हम बापू जी ने पूरे जीवन पर गौर करें तो कोई एक प्रसंग ही नहीं, अपितु उनका संपूर्ण जीवन, यहां तक कि दैनिक जीवन, आचार–विचार, आदत–व्यवहार आदि सभी प्रेरणादायक हैं। उन्हें दिखावा तो रति मात्र भी पसंद नहीं था। वे जो करते थे, पहले स्वयं प्रयोग करते थे। गांधी जी का दर्शन कहें या उनका संदेश था–हिंसा विहीन मानना, प्रदूषण विहीन पर्यावरण, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर शोषण विहीन समाज और न्याय के लिए अग्रसर रहना चाहिए। करूणा, क्षमा, निर्भयता और जिम्मेदारी ये सभी अहिंसा के अंग हैं जो गांधी जी दर्शन है, उन्हें सदैव अपनाने की जरूरत है।

विद्यार्थी भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन

दिनांक 23.10.2024 : हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ लि. (हरकोफैड), पंचकूला विद्यार्थी भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत जाट हाई स्कूल रोहतक, जिला रोहतक के कक्षा 11वीं, 12वीं के 21 विद्यार्थियों व 02 टीचरों को जिला की सहकारी संस्थाओं और समितियों का भ्रमण कराया गया।

श्रीमती अर्चना देवी शिक्षा अनुदेशक हरकोफैड रोहतक ने विद्यार्थियों को सहकारिता समितियों की कार्यप्रणाली व गतिविधियों से अवगत कराने के उद्देश्य से हैफेड, कैटल फीड प्लांट का भ्रमण करवाते हूए दिखाया व बताया कि कैसे प्लांट में गेहूं, बाजरा, सोयाबीन, मक्का आदि अनाज, सरसों खल को मिक्स पीसकर उसमें राला व नमक की उचित मात्रा मिलाकर पशुओं के लिए संतुलित आहार बनाया जाता है।

मैडम साक्षी अहलावत ने भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को बारीकी से समझाया कि कैसे गांव स्तर से दुध इकठठा व टैस्टींग कर के ब्लॉक लेवल पर चिलिंग सैन्टरो तक जाता है और वहां से वीटा प्लांट तक इंसुलेटिड वाहन द्वारा पहुंचाया जाता है। प्लांट में फिर टेस्टींग के बाद पॉश्राजर के बाद दुध की क्रीम निकालना अलग–अलग टोन की पैकिंग, दही जमाना, लस्सी बनाना, घी बनाना आदि और पैकिंग करना दिखाया व बताया गया। इस दौरान प्लांअ की विभिन्न युनिटों का दौरा कराते हुए बच्चों की विभिन्न शंकाओं का समाधान किया।

भ्रमण कार्यक्रम के अगले पडाव में दि रोहतक केन्द्रिय सहकारी बैंक, रोहतक का भ्रमण कराया गया इसमें बैंक के श्री प्रवीन सीनियर अकाउंटेंट ने सैन्ट्रल सोसाइटी के तौर पर कार्य कर रही बैंक की गतिविधियों बारे विस्तार से समझाया व दिखाया। उन्होंने बैंक द्वारा दी जा रही विभिन्न ऋण स्कीमों की जानकारी देते हुए इन स्कीमों का कैसे लाभ लिया जा सकता है बारे समझाया। उन्होंने बच्चों को गुडपे मास्टर बनने हेतू प्रेरित किया।

पारंपरिक कृषि के मुकाबले जैविक कृषि के फायदे

रक्षित मैहल, सुमित मैहला, निशु, रोबिन
चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

जैविक कृषि और पारंपरिक कृषि दो मुख्य कृषि पद्धतियाँ हैं, जो विभिन्न तरीकों से भोजन और अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादों का उत्पादन करती हैं। जैविक खेती, जैसा कि नाम से पता चलता है, जैविक तत्वों पर आधारित होती है और इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता। आइए आज हम जैविक कृषि के फायदे पारंपरिक कृषि के मुकाबले जानते हैं।

1. पर्यावरण के लिए लाभकारी : जैविक खाद, केंचुए और सूक्ष्मजीवों की गतिविधि से मिट्टी की संरचना और जलधारण क्षमता में सुधार होता है। निम्नलिखित बिंदु पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं।

जल प्रदूषण में कमी : जैविक खेती जल प्रदूषण के मामले में पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। इसमें रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग नहीं होता, जिससे जल स्त्रोतों में प्रदूषण कम होता है। यह जल का संरक्षण करता है, जिससे नदियों और झीलों की स्वच्छता बनी रहती है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग भूजल और नदियों को प्रदूषित करता है।मिट्टी की सेहत में सुधार : कृषि में जैविक खेती में फार्म यार्ड खाद और जैविक उर्वरक का उपयोग पोषण पुनर्चक्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। जैविक खेती जल प्रदुषण को कम करने में सहायक होती है।

वायु प्रदूषण में कमी : रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग से हानिकारण गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। जैविक खेती वायु प्रदुषण को कम करने में योगदान देती है।

जैव विविधता का संरक्षण : जैविक खेती में रासायनिक पदार्थो का प्रयोग नहीं होता है, जिससे मिट्टी में सूक्ष्मजीवों, पक्षियों और कीटों की जैव विविधता बनी रहती है। (जैविक नाइट्रोजन–फिक्सिंग बैक्टीरिया) ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में परिवर्तित करते हैं, जिससे पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। ये जड़ प्रणाली के साथ मिलकर पौधों की पोषण अवशेषण क्षमता को बढ़ाते हैं। (फंगल माइकोराइजा)

स्वास्थ्यवर्धक भोजन : जैविक खेती से उत्पादित फसलों में रसायनों की मात्रा कम होती है, जिससे स्वास्थ्यवर्धक और सुरक्षित भोजन उपलब्ध होता है।क्लाइमेट चेंज से लड़ना :

जैविक खेती कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने और मिट्टी में कार्बन की संरक्षित करने में सहायक होती है।

2. मृदा की गुणवत्ता में सुधार : जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक खाद (कंपोस्ट, वर्मीकंपोस्ट, गोबर खाद आदि) का उपयोग किया जाता है। यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाता है, जिससे मिट्टी की संरचना बेहतर होती है, संरचना बेहतर होती है, जलधारण क्षमता बढ़ती है और मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ता है।

सूक्ष्मजीवी की गतिविधि : जैविक खेती मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्मजीवों की गतिविधि को बढ़ावा देती है। ये सूक्ष्मजीव मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करने, पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने और मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

केंचुए : जैविक खेती में केंचुओं की संख्या बढ़ती है। केंचुए मिट्टी को छेदकर उसे हवादार बनाते हैं, जिससे मिट्टी की जल निकासी और जलधारण क्षमता में सुधार होता है। वे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थो को मिलाकर उसे उर्वर बनाते हैं।

मिट्टी की संरचना : जैविक खेती में मिट्टी की संरचना बेहतर होती है, जिससे पानी और हवा का संचार सुचारू रूप से हो पाता है। यह पौधों की जड़ों के विकास और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ावा देता है।

रसायनों का अभाव : रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को कम करता है, सूक्ष्मजीवों की गतिविधि को बाधित करता है और मिट्टी की संरचना को नुकसान पहुँचाता है। जैविक खेती में इन रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे मिट्टी की सेहत सुधार होता है।

3. मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद :

रसायनों से मुक्ति : जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है, जिससे उत्पादित खाद्य पदार्थों में रसायनों की मात्रा कम होती है। जैविक खेती से उत्पादित फसलों में प्राकृतिक रूप से अधिक पोषक तत्व, जैसे विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।

एलर्जी और विषाक्ता का कम खतरा : रसायनों के अत्यधिक उपयोग से एलर्जी, विषाक्त और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएँ हो सकती हैं। जैविक खेती से इन खतरों को कम किया जा सकता है।

पेट स्वास्थ्य में सुधार : जैविक खेती से उत्पादित खाद्य पदार्थों में लाभकारी बैक्टीरिया अधिक होती हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते है।

प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना : जैविक खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्साडेंट और अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और बीमारियों से लड़ने में मदद करते है।

लंबी अवधि के स्वास्थ्य लाभ : जैविक खेती से उत्पादित खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन लंबी अवधि में स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है, जैसे कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह के खतरे को कम करना। स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व, जैविक खेती से उत्पादित फसलों में प्राकृतिक रूप से अधिक पोषक तत्व, जैसे विटामिन, खनिज ओर एंटीऑक्साडेंट पाए जाते हैं।

एलर्जी ओर विषाक्ता का कम खतरा : रसायनों के अत्यधिक उपयोग से एलर्जी, विषायक्ता और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएँ हो सकती हैं। जैविक खेती से इन खतरों को कम किया जा सकता है।

4. स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन : छोटे किसानों का उत्थान : जैविक खेती से उत्पादित फसलों की मांग अधिक होती है, क्योंकि वे स्वास्थ्यवर्धक, स्वादिष्ट और रसायन मुक्त होते हैं। जैविक उत्पादों के लिए बाजार मूल्य पारंपरिक उत्पादों की तुलना में अधिक होता है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है।

प्रमाणित बाजार : जैविक खेती के लिए प्रमाणन प्रणाली उपलब्ध है, जिससे किसान अपने उत्पादों को प्रमाणित जैविक उत्पाद के रूप में बेच सकते हैं। प्रमाणित जैविक उत्पादों की मांग और मूल्य उच्च होता है।

सीधा बाजार : जैविक खेती करने वाले किसान अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं या खुदरा विक्रेताओं को बेच सकते हैं, जिससे बिचैलिए की कमी के कारण अधिक आय प्राप्त होती है।

कम उत्पादन लागत : जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता है, जिससे उत्पादन लागत कम होती है।

विविधतापूर्ण खेती : जैविक खेती में किसान विभिन्न प्रकार की फसलों और पशुधन पालन कर सकते हैं, जिससे उनकी आय में विविधता आती है।

रोजगार के अवसर : जैविक खेती, पारंपरिक खेती के मुकाबले, रोजगार के अवसरों का एक खजाना खोलती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए गए है :

जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग : जैसे–जैसे जैविक खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है, किसानों को अपने उत्पादों को उगाने, संसाधित करने, पैक करने और वितरित करने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। इससे किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होते है, जैसे :

- खेत मजदूर : फसलें बोना, काटना, निराई करना और फसलों की देखभाल करना।
- प्रसंस्करण कर्मचारी : जैविक उत्पादों को छँटना, साफ करना, पैकिंग करना और संसाधित करना।
- बिक्री और मार्केटिंग : ग्राहकों से सीधे संपर्क करना या किसान बाजारों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और रेस्टोरेंटों के माध्यम से उत्पादों को बेचना।
- जैविक आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार : बड़े जैविक खेतों और व्यवसायों को रसद, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण नेटवर्क के प्रबंधन के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

- जैविक कृषि में विशेषज्ञता की मांग : जैविक खेती में विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे :
- खाद बनाना और जैविक उर्वरक का उत्पादन : इससे खाद विशेषज्ञों, वर्मीकंपोस्ट विशेषज्ञों और जैव उर्वरक उत्पादन से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
- कीट और रोग प्रबंधन : जैविक कीट नियंत्रण विधियों (जैसे – लाभकारी कीड़े, फसल चक्र और जैविक स्प्रे) के लिए कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
- मिट्टी के स्वास्थ्य का प्रबंधन : मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किसानों और तकनीशियनों की आवश्यकता होती है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और मिट्टी का क्षरण रोका जा सके।
- प्रशिक्षण और प्रमाणन : जैविक खेती के विकास के साथ, अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रमाणन निकाय उभरते हैं, जिससे प्रशिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं और प्रशासकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
- मूल्य वर्धित प्रसंस्करण : जैविक खाद्य पदार्थों में अवसर मूल्य वर्धित प्रसंस्करण शामिल होता है, जैसे :
- जैविक खाद्य प्रसंस्करण : जैविक उत्पादों से जैम, सॉस, अचार, सूखे माल और अन्य मूल्य वर्धित उत्पाद बनाना।
- जैविक पशुधन : जैविक पोल्ट्री, डेयरी गायों और सूअरों को पालने के लिए जानवरों की देखभाल, चारा तैयार करने और प्रसंस्करण के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है।
- स्थानीय खाद्य प्रणालियाँ : जैविक खेती स्थानीय खाद्य प्रणालियों के विकास में योगदान देती है, जिससे किसान बाजारों, खाद्य केंद्रों और सामुदायिक–समर्थित कृषि (सीएसए) कार्यक्रमों को समर्थन मिलता है, जो बाजार प्रबंधकों, वितरण चालकों और सामुदायिक आयोजकों के लिए रोजगार के अवसर करते हैं।

5. जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई : जैविक खेती, पारंपरिक खेती के मुकाबले, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में एक शक्तिशाली हथियार साबित हो रही है। यहाँ कुछ प्रमुख तरीके बताए गए हैं।

कार्बन सिंक के रूप में मिट्टी : कार्बन संचयन जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण लाभ है, जो इसे पारंपरिक खेती पर प्राथमिकता देने का एक कारण बनाता है। जैविक खेती में जैविक खाद और केंचुओं की गतिविधि से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है। यह मिट्टी को कार्बन सिंक में बदल देता है, जिससे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर उसे मिट्टी में जमा किया जा सकता है। पारंपरिक खेती में रसायनों का उपयोग मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को कम करता है, जिससे मिट्टी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है।

जल संरक्षण और मिट्टी स्वास्थ्य : जैविक खेती में मिट्टी की संरचना बेहतर होती है, जिससे पानी को सोखने और धारण करने की क्षमता बढ़ती है। यह सूखे के प्रभावों को कम करता है और जल संसाधनों को संरक्षित करता है। जैविक खेती मिट्टी का क्षरण रोकने में मदद करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है।

जैव विविधता का संरक्षण : जैविक खेती में पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे कीटों, पक्षियों और अन्य सूक्ष्मजीवों की आबादी को संरक्षित किया जा सकता है।

बच्चे हमारे आचरण से सीखते हैं, उपदेश से नहीं

जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम अपने बच्चों से भी अपेक्षा करते हैं कि वे भी घर आए मेहमानों का उचित रीति से अभिवादन करें। एक बार एक महिला अपनी एक मित्र के घर गई। मेजबान मित्र ने अपनी नन्ही–सी पोती से कहा कि आंटी को नमस्ते करो। सहमी हुई सी बच्ची ने मुँह फेर लिया। उसकी दादी ने बच्ची का मुँह मेहमान की ओर घुमाते हुए बच्ची से फिर कहा कि आंटी को नमस्ते करो। बच्ची को नमस्ते नहीं करनी थी सो नहीं की। दादी ने बच्ची को डाँटते हुए कहा, ''गंदी बच्ची नमस्ते करना भी नहीं जानती, भाग यहाँ से।'' बच्ची रुआँसी–सी होकर वहाँ से चली गई। बच्ची ने घर आए हुए मेहमान का अभिवादन क्यों नहीं किया इससे पहले ये सवाल उठता है कि क्या एक छोटे बच्चे के लिए घर आए हर मेहमान का अभिवादन करना जरूरी है और वो भी जैसे हम चाहें?

बच्चे घर आए हर मेहमान का अभिवादन करें ये अच्छी बात है लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम जिस रूप में चाहें उसी तरह से बच्चे भी आगंतुकों का सम्मान करें। हम प्रायः बच्चों को अपने ढंग से संस्कारित करने का प्रयास करते हैं। उन्हें कहते हैं कि ऐसा करो या ऐसा मत करो। सारे दिन उपदेश देते रहते हैं। बच्चा इन उपदेशों से दुखी–सा रहने लगता है। कई व्यक्ति खुद तो मेहमानों का यथोचित स्वागत अथवा अभिवादन नहीं करते, लेकिन अपने बच्चों से चाहते हैं कि वे हर आने–जाने वाले का स्वागत व अभिवादन ठीक से करें। जहाँ तक बहुत छोटे बच्चों का संबंध है उनका बड़ों की ही तरह स्वागत या अभिवादन करना बिलकुल जरूरी नहीं। इसका ये अर्थ नहीं है कि बच्चे आगंतुकों से मिलें ही नहीं या मिलने पर चुप रहें।

क्या बच्चे मेहमानों से मिलना–जुलना या उनका प्यार पाना व उनका अभिवादन करना नहीं चाहते? बच्चे भी सबसे मिलना–जुलना व उनका अभिवादन करना चाहते हैं लेकिन अपने तरीके से। हो सकता है बच्चा संकोच कर रहा हो अतः उसे कुछ समय देना चाहिए। संकोच के समय बच्चे से बलपूर्वक कुछ करवाना उसे जिद्दी बनाना है। बच्चों की अपनी दुनिया होती है। वे अपने ढंग से शुरुआत करना चाहते हैं। कई बार वे शब्दों से नहीं अपने कार्यों से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। बच्चों का मेहमानों या आगंतुकों के लिए पानी या जलपान स्वयं ले जाने की जिद करना उनका अभिवादन करने का तरीका ही तो है। आप मेहमानों के लिए पानी या नाश्ता वगैरा ले जाते हैं तो बच्चा भी ऐसा ही करने की कोशिश करता है। तो आप अपने बच्चों से मेहमानों का जैसा स्वागत–सत्कार करवाना चाहते हैं वैसा ही आप स्वयं कीजिए।

यदि हममें शिष्टाचार है तो हमारे बच्चे भी वही शिष्टाचार अपना लेंगे। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए माता–पिता व दादा–दादी को बच्चों से जिद करने की बजाय मेहमानों के सामने स्वयं आदर्श व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई किताब या पाठ्यक्रम नहीं है जो बच्चों को शिष्ट, व्यवहारकुशल व नैतिक बना सके। नैतिक शिक्षा देना एक भूल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। दादा–दादी, माता–पिता, चाचा–ताऊ, बड़े भाई–बहन व अन्य नजदीकी रिश्तेदारों से ही बच्चा शिष्टाचार व नैतिकता ग्रहण करता है और उसे अपने जीवन में उतारता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिष्ट, व्यवहारकुशल और नैतिक गुणों से संपन्न हों तो हमें अनिवार्यतः स्वयं में इन गुणों को विकसित करना चाहिए।

आशा गुप्ता, ए.डी. 106 सी., पीतमपुरा, दिल्ली – 110034, मोबा0 नं0 9310172323, Email : srgupta54@yahoo.co.in

एसबीएम ने खोला कचरे से कमाई का रास्ता

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) की शुरूआत 10 साल पहले हुई थी। 1.45 अरब लोगों के देश में किसी भी योजना को लागू करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच समन्वय की जरूरत होती है। दशक भर की यात्रा पर नजर डालें तो स्वच्छ भारत मिशन ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है।

हर क्षेत्र में असर : स्वच्छ भारत मिशन का मकसद था कि यह देश के हर कोने तक पहुंचे। स्वच्छता का असर स्वास्थ्य और लोगों की सुरक्षा पर भी पड़ता है। इस मिशन ने सभी क्षेत्रों पर अपना असर छोड़ा है। स्थानीय सरकार और लोगों के बीच सहयोग पर ध्यान केन्द्रित करके स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में असर दिखाया है।

शौचालय बनाने पर ध्यान : मिशन ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का अंतराल कम हो और उपलब्ध सेवाएं बराबर मिलें। एसबीएम–ग्रामीण ने खुले में शौच को खत्म करने, 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करने और स्वच्छता जागरूकता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित किया।

स्थिति में सुधार : अंबिकापुर का मामला ऐसे कई मूल मूल्यों को उजागर करता है, जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन ने भारत की हर नगरपालिका में बनाए रखने की कोशिश की है–सहयोग, श्रम की गरिमा और इनोवेशन। पिछले एक दशक में मिशन की कुछ सबसे जरूरी प्राथमिकताएं सीवेज कर्मचारियों की कार्य स्थिति में सुधार लाना, सीवेज की सफाई को पूरी तरह से स्वचालित बनाना, हाथ से कचरा ढोने की प्रथा को रोकना और अपशिष्ट निपटान के पीछे के अर्थशास्त्र को उलट कर देशभर में लैंडफिल को ठीक करना रही है।

जीरो डंप साइट : 2022 में शुरू किए गए, लक्ष्य जीरो डंप साइट चुनौती के तहत, देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों ने मौजूदा डंप साइट को बंद करने, वैज्ञाकि लैंडफिल को बनाए रखने और देशभर में सभी अवैध डंप साइट को ठीक करने की दिशा में काम किया है।

लक्ष्य पूरे हो रहे : स्वच्छ भारत मिशन ने कचरे से कमाई पर बहुत ध्यान दिया है। इसका मतलब है कि नए वेस्ट मैनेजमेंट के जरिये कचरे को फिर से इस्तेमान की जा सकने वाली चाजों में बदलना। इस पहल ने रीसाइक्लिंग, कचरे से खाद, बायोगैस और बिजली बनाने को प्रोत्साहित किया है। इससे कचरे का निपटारा पहले से बढ़ गया है। इस तरह से लैंडफिल दबाव को कम करने में मदद मिली है। साथ ही, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी फायदा हो रहा है।

मंत्रालयों में सहयोग : स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच जिस तालमेल से काम को रहा, वह देखना उत्साहजनक है। कचरे से बिजली बनाने के लिए एसबीएस ने बिजली मंत्रालय के साथ काम शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि शहरी कचरे से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। इसी तरह, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बढ़ावा देना। इसी तरह, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग करना शुरू कर दिया। कृषि मंत्रालय ने शहरी कम्पोस्ट योजना की शुरूआत के साथ नगर निगम के ठोस कचरे से खाद के उपयोग को बढ़ावा देना शुरू किया।

नागरिकों की भागीदारी : मिशन का शायद सबसे उत्साहजनक पहलू नागरिकों की उत्साही भागीदारी रही है। यह मिशन वास्तव में जन आंदोलन बन गया है।

किरायेदारों को जीरो डिपाजिट पर मकान दिलाएगी सर्किल पे : आईआईटी और आईआईएम के छात्रों द्वारा स्थापित कंपनी सर्किल पे ने अपने नवाचार के माध्यम से किराए पर मकान लेते वक्त पारंपरिक सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत को खत्म करने का ऐलान किया है।

कंपनी के सह संस्थापक श्री नवन जायसवाल ने कहा कि बहुत से ऑनलाइन लिस्टिंग मार्केटप्लेस किराएदारों को प्रॉपर्टी खोजने में मदद करते हैं, लेकिन सर्किल पे उनसे अलग है क्योंकि यह विशेष रूप से किराएदारों को बिना सिक्योरिटी डिपाजिट के उनकी पसंद की प्रॉपर्टी में पहली बार में ही शिफ्ट होने में मदद करता है।

सर्किल पे यह काम महान मालिक को पूरी लीज राशि एडवांस में देकर और किसी भी संभावित क्षति के लिए कंपनी द्वारा समर्थित गारंटी प्रदान करके करता है। यह मकान मालिकों के लिए डिपाजिट की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे किराएदार आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं और मासिक किराया देना जारी रख सकते हैं। कंपनी का लक्ष्य है कि 2025 तक 10,000 किरायेदारों को जीरो सिक्योरिटी डिपाजिट पर शिफ्ट करने में मदद मिले, साथ ही मकान मालिकों को 100 करोड़ रूपये एडवांस किराए के रूप में दिया जाए। श्री जायसवाल ने कहा कि 'सर्किल पे में, हमारा लक्ष्य है कि भरोसेमंद किराएदारों के लिए वित्तीय तनाव को दूर करना है, जिससे वे बिना भारी सिक्योरिटी डिपाजिट के अपने मनपंसद घर में शिफ्ट हो सकें। इसके साथ ही मकान मालिक भी एडवांस में पूरा किराया प्राप्त करते है और संभावित नुकसान के लिए उन्हें गांरटी मिलती है।'

कंपनी के सह–संस्थापक श्री अंकुर यादव ने कहा कि मकान मालिक अक्सर अस्थिर किराएदारों और किराए के भुगतान की व्यवस्था से जूझते हैं। हमारा माडल उन्हें

संभावित जोखिमों जैसे संपत्ति क्षति या प्रारंभिक रिक्तियों से सुरक्षित रखता है। यह दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा है।

2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनामी बनने की तरफ बढ़ रहा भारत : भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। रेटिंग एजेंसी ने हालांकि कहा कि बढ़ती जनसंख्या बुनियादी सेवा का दायरा बढ़ाने में बढ़ती चुनौतियों को प्रस्तुत करती है और उत्पादकता बनाए रखने के लिए निवेश की बढ़ती जरूरतें भी सामने आती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अगले दशक और उससे आगे के लिए उच्च महत्वाकांक्षाए हैं। वर्तमान में 3600 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनना का लक्ष्य 2047 तक 30 हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनना है। भारत इस समय दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

एसएंडपी ने कहा, 'भारत अगले तीन साल में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और 2030 तक वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। निवेश बैकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन के 'सरकारी उभरते बाजार बांड सूचकांक' में 2024 में इसका प्रवेश अतिरिक्त सरकारी वित्तपोषण प्रदान कर सकता है और घरेलू पूंजी बाजारों में महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच बना सकता है।' एसएंडपी ने अपनी 'उभरते बाजारों पर भविष्य की नजर : एक निर्णायक दशक' रिपोट में कहा कि उभरते बाजार अगले दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जहां 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 'औसत वृद्धि दर 4.06 प्रतिशत रहेगी वहीं उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह दर 1.59 प्रतिशत रहेगी। साल 2035 तक उभरते बाजार वैश्विक आर्थिक वृद्धि में लगभग 65 प्रतिशत का योगदान देंगे। इस वृद्धि में मुख्य रूप से एशिया–प्रशांत क्षेत्र की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का योगदान होगा। इनमें चीन, भारत, वियतनाम और फिलिपीन शामिल हैं।

एसएंडपी ने कहा 'इ आलाव, 2035 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाएगा, जबकि इंडोनेशिया और ब्राजील क्रमश : आठवें और नौवें स्थान पर होगे।' इसमें कहा गया है कि भारत ने अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर अपनी कमजोर राजकोषीय क्षमता को सुधारने के लिए भी कदम उठाए है, जिससे दीर्घकालिक वृद्धि को और अधिक समर्थन मिलेगा।

रहने को नहीं, किराये को संपत्ति खरीद रहे हैं निवेशक : देश में रियल एस्टेट बाजार मुनाफा कमाने के लिये निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। रियल एस्टेट बाजार में निवेशकों की प्राथमिकताएं अब बदल रही हैं। शहरों में निवेशक अब किराये से आय कमाने के लिए संपत्ति में निवेश करना पसंद करते हैं जबकि अब पूरी तरह तैयार रेडी टू मूव आवासों के बजाय 3 बीएचके के बड़े आवासों की मांग बढ़ रही हैं खरीदारों का औसत बजट 45 से 90 लाख रूपये है। यह खुलासा रियल एस्टेट बाजार को लेकर तैयार की गई फिक्की व एनारोक की 'होमबॉयर संेटीमेंट सर्वे–2024' रिपोर्ट में हुआ है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैबर्स ऑफ कामर्स एंड इडंस्ट्री (फिक्की) और एनररोक प्रापर्टी कंसल्टेंट्स की ओर से हाल ही में फिक्की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 'होमर्बायर संेटीमेंट सर्वे–2004' रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में देश में रियल एस्टेट सेक्टर की मौजूदा स्थिति, आवासों की मांग, बाजार में हो रहे बदलावों तथा खरीददारों की प्राथमिकताओं का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में 59 प्रतिशत लोगों ने माना कि रियल एस्टेट क्षेत्र निवेश के लिये सबसे पंसदीदा क्षेत्र बना हुआ है। शहरों में किराये से आय कमाना निवेशकों की पसंद बन रहा है। सर्वे में 57 प्रतिशत खरीददारों ने स्वीकार किया कि शहरों में बढ़ती किराये की दरों से प्रेरित होकर किराये की आय अर्जित करने के लिए संपत्ति खरीद रहे हैं।

सर्वे के अनुसार हाल के वर्षों में रियल एस्टेट बाजार में तैयार घरों की मांग में काफी गिरावट आई है। तैयार घरों और नए लांच का अनुपात अब 20 : 25 है, जबकि 2020 में यह 46 : 18 था। सर्वे के अनुसार 51 प्रतिशत निवेशकों की पहली पंसद 3 बीएचके वाले बड़े आवास हैं। सर्वे में सर्वाधिक 35 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनका औसत बजट 45 से 90 लाख रूपये है लेकिन उनका रूझान प्रीमियम संपत्तियों की ओर है। सर्वे में 28 प्रतिशत लोगों ने आवासा खरीदने के लिए अपना बजट 90 लाख और 1.5 करोड़ रूपये के बीच बताया। दक्षिण भारत के शहरों खरीददारी के लिये 58 प्रतिशत लोगों की पसंद अपार्टमेंट तथा आवासीय भूखंड है। खरीददारों में 98 प्रतिशत का मानना है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना चाहिए जबकि 93 प्रतिशत ने बेहतर निर्माण गुणवत्ता तथा 72 प्रतिशत ने हवादार आवास को अपनी पंसद बताया। सर्वे के अनुसार 67 प्रतिशत खरीदार अपने उपयोग के लिए संपत्ति खरीदते हैं, जबकि 33 प्रतिशत निवेश के लिये संपत्ति खरीद रहे हैं। होम लोन की दरों से संबंधित सवाल पर सर्वे में 71 प्रतिशत खरीददारों का कहना है कि 8.5 प्रतिशत की दर का आवास खरीदने पर कम असर होगा लेकिन 87 प्रतिशत लोगों का कहना है कि यदि होम लोन दरें 9 प्रतिशत या इससे अधिक होती हैं, तो इससे खरीद पर व्यापक असर पड़ेगा।

प्रैस कतरनें

वैली ग्राउंड में प्रदर्शनी का अवलोकन कर मुख्यमंत्री ने बढ़ाया लोगों का उत्साह

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह के दौरान लेजर वैली ग्राउंड में सहकारिता समितियों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शनी लगाने वाले अधिकतर लोगों से संवाद किया। उनसे उनकी आय के बारे में पूछा। यही नहीं, उन्हें सरकार की ओर से सहयोग करने का आश्वासन दिया। इससे सभी खुश नजर आए। प्रदर्शनी में लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। पीतल की थाली एवं पीतल की ज्योत की मांग काफी अधिक दिखी। इनके अलावा विभिन्न प्रकार के आचारों व अन्य सामानों को खरीदने वालों की भी अच्छी संख्या दिखी।

गुरुग्राम के सेक्टर 29 के लेजर वैली मैदान पर राज्य स्तरीय सहकारिता समारोह में उपस्थित लोगों का अभिवादन स्वीकार करते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, साथ में सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डा. अरविंद शर्मा साथ अन्य • जागरण

प्रदर्शनी का अवलोकन करने के दौरान एक स्टाल पर लड्डू खाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एवं सहकारिता मंत्री डा. अरविंद शर्मा • जागरण

सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुति देते कलाकार • जागरण

प्रदर्शनी में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि इस प्रकार के आयोजन समय-समय पर होने चाहिए। इससे उनलोगों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का बेहतर मौका मिलता है। कुछ लोगों ने कहा कि सस्ते दर यदि बैंक लोन उपलब्ध कराएं तो सहकारिता समितियां और बेहतर कर सकती हैं। अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने पहुंचे पीतल नगरी रेबाड़ी के उद्यमी इंदरपाल सिंह मल्होत्रा ने कहा कि पीतल के सामानों की मांग फिर से बढ़ रही है। खासकर पंजाब एवं गुजरात में काफी मांग है। दीपावली के दौरान हरियाणा में भी काफी मांग रहती है। यदि बैंक सस्ते दर पर लोन उपलब्ध कराएं तो वे लोग और बेहतर कर सकते हैं। प्रदेश सरकार बैंकों से सस्ते दर पर लोन उपलब्ध कराए। साथ ही समय-समय पर प्रदर्शनी का आयोजन कराए। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार और अधिक प्रयास करेगी। सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी।

सांस्कृतिक कार्यक्रम ने मन मोह लिया : समारोह के दौरान हरियाणवी कलाकारों ने अपने प्रस्तुतियों से हर किसी का मन मोह लिया। प्रस्तुति के दौरान मुख्यमंत्री मंद-मंद मुस्कुराते रहे। खासकर मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे भजन सुनाकर, कलाकारों ने समारोह में उपस्थित हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने सहकारिता विभाग की उपलब्धियों को भी अपने भजनों के माध्यम से प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने अंत में कलाकारों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान जय श्रीराम के उद्घोष से कई बार पंडाल गूंजा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एवं सहकारिता मंत्री डा. अरविंद शर्मा ने भी जय श्रीराम का उद्घोष किया।

नारायणगढ़ में अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल होगी स्थापित: नायब सिंह सैनी

विकसित भारत-विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने के लिए सहकारिता समितियों से जुड़ने का किया आह्वान

राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में संबोधित करते सीएम नायब सिंह सैनी।

गुड़गांव, 21 नवम्बर (ब्यूरो): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहकारिता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए लोगों से विकसित भारत-विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने में सहकारी समितियों से सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री गुरुग्राम में 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि नारायणगढ़ में जल्द ही एक नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी।

इसके अलावा, कुरुक्षेत्र में एक आधुनिक सूरजमुखी तेल पेराई मिल स्थापित की जाएगी और रेवाड़ी में देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल स्थापित की जाएगी। विकसित भारत-विकसित हरियाणा के संकल्प को पूरा करने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने व्यापक सुझाव दिए, जिनमें स्थानीय उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच, किसानों को लाभान्वित करने के लिए फसल भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की सुविधाएं स्थापित करना, महिला स्वयं सहायता समूहों का कौशल विकास और वित्तीय साक्षरता देना शामिल है। उन्होंने युवाओं के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ-साथ परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली और ई-गवर्नेंस प्रथाओं को अपनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने सार्वजनिक-निजी भागीदारी ...

Power Grid allocates ₹50 cr to renovate cremation sites

Leena Dhankhar
leena.dhankhar@hindustantimes.com

Haryana CM Nayab Singh Saini at the 71st National Cooperative Week in Gurugram on Thursday. PARVEEN KUMAR/HT

GURUGRAM: The Power Grid Corporation, one of the country's Navratna companies, has allocated ₹50 crore under its Corporate Social Responsibility (CSR) scheme to renovate cremation grounds and burial sites across 658 villages in Haryana. The initiative, undertaken under the Shiv Dham Project, will cover the districts of Karnal, Panipat, Rewari and Kurukshetra, benefitting a population of nearly 40 lakh in the state.

A Memorandum of Understanding (MOU) for the project was signed between Power Grid and the Department of Development and Panchayats in the presence of Haryana chief minister Nayab Singh Saini in Gurugram. The CM praised the role of companies in rural development through CSR initiatives, calling it a commendable step towards social empowerment.

The MOU was signed by Dr J K Abhir, Director General of the Development and Panchayat Department and Sanjay Kumar Verma, General Manager of Power Grid. Under the project, cremation grounds and burial sites will be equipped with boundary walls, paved pathways, sheds, and drinking water facilities.

As part of the project, ₹10.98 crore will be spent on 198 villages in Karnal, ₹18.46 crore on 237 villages in Kurukshetra, ₹5.15 crore on 106 villages in Panipat, and ₹15.35 crore on 117 villages in Rewari. Power Grid Chairman and Managing Director R K Tyagi said that the project would cost ₹49.94 crore.

The initiative is aimed at improving infrastructure and accessibility in rural areas.

"Since the formation of the Haryana CSR Board in November 2018, which was upgraded to the Haryana State CSR Trust in March 2021, ₹750 crore worth of development projects have been executed under social participation programs. For the current financial year, ₹350 crore has been allocated for similar initiatives," he said.

The Shiv Dham Project is part of Haryana's broader social development initiatives.

In a separate development, the number of MBBS seats in medical colleges increased to 2,185 earlier is expected to go up to 3,485 over the next few years. The CM said that the number of MBBS seats in medical colleges has been increased from 700 to 2,185, while the number of PG seats has risen from 289 to 861. Additionally, there are now 155 seats for PG diploma courses. Over the next 3-4 years, the number of MBBS seats is expected to increase to 3,485. It has also been decided that nursing, physiotherapy and paramedical departments will also be established in every medical college of the state, he added.

AIIMS in Rewari district

The chief minister said that the government has taken over the closed Gold Field Medical College in Chhayansa in Faridabad, and re-started it in the name of former PM Atal Bihari Vajpayee. The National Cancer Institute has already been opened in Badhsa in Jhajjar, while AIIMS is being established in Majra, of Rewari district.

रेवाड़ी में सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल स्थापित होगी : मुख्यमंत्री

घोषणा

गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रेवाड़ी में देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को गुरुग्राम में 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि नारायणगढ़ में जल्द ही एक नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी। इसके अलावा, कुरुक्षेत्र में एक आधुनिक सूरजमुखी तेल पेराई मिल स्थापित की जाएग। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच, किसानों को लाभान्वित करने के लिए फसल भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की सुविधाएं स्थापित करना, महिला स्वयं सहायता समूहों का कौशल विकास और वित्तीय साक्षरता देना शामिल है। उन्होंने युवाओं के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ-साथ परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली और ई-गवर्नेंस प्रथाओं को अपनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत काम करने का भी आग्रह किया। ये पहलें न केवल सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देंगी बल्कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत और समृद्ध हरियाणा के विजन में भी सहायक होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी समितियां कृषि और ग्रामीण विकास व राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने हरियाणा में विभिन्न उत्पादों के लिए अमूल व अन्य की तरह एक एकीकृत ब्रांड बनाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सहकारिता के लिए एक व्यापक कार्य योजना विकसित करके हम श्री अन्ना जैसे स्थानीय बाजरे को बढ़ावा दे सकते हैं और उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह की थीम विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन रखा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सहकारिता से समृद्धि का मंत्र इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए: सीएम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सहकारिता से जुड़े लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की सहकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 40 पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी 19 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने राज्यभर में 7 लाख से अधिक किसानों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं।

दुबई से मिले ऑर्डर : मुख्यमंत्री ने कहा कि हैफेड को दुबई और अन्य देशों से बासमती चावल के निर्यात के लिए ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसमें 1200 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 1 लाख मीट्रिक टन चावल निर्यात किया गया है। हैफेड ने रेवाड़ी और नारनौल में नई तेल मिलें, साथ ही रादौर में हल्दी का प्लांट भी स्थापित किया है। रोहतक में 180 करोड़ रुपये की लागत से मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। चीनी मिलें 360 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करके इस सीजन में 35 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है।

गुरुग्राम में आयोजित 71वें सहकारिता सप्ताह के राज्यस्तरीय समापन समारोह में गुरुवार को लोगों का अभिवादन करते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।

सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार तत्पर

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने राज्य भर में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों से सहकारी ढांचे को मजबूत करने, स्थानीय समुदायों की क्षमताओं को बढ़ाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में, हरियाणा में लगभग 33,000 कार्यात्मक सहकारी समितियां हैं, जिनमें लगभग 55 लाख लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गांव में एक सहकारी समिति या पैक्स होनी चाहिए।

पॉवरग्रिड और पंचायत विभाग के बीच एमओयू

भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक पॉवरग्रिड द्वारा सीएसआर के अंतर्गत करीब 50 करोड़ रुपए की राशि से हरियाणा के चार जिलों करनाल, पानीपत, रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र के 658 गांवों में शिवधाम योजना के तहत शमशान घाट और कब्रिस्तान का पुनरुद्धार करवाया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में पॉवरग्रिड और विकास एवं पंचायत विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएसआर के अंतर्गत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कॉरपोरेट कंपनियां अतुलनीय योगदान दे रही हैं, जो सामाजिक उत्थान की दिशा में सराहनीय कदम है। इस अवसर पर वाणिज्य, उद्योग, वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह, सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा भी उपस्थित रहे। एमओयू पर विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक डॉ जेके अभीर और पॉवरग्रिड की ओर से महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा ने हस्ताक्षर किए।

71वें राज्य स्तरीय सहकारिता समापन समारोह में सामुदायिक विकास के महत्व को दी एक नई दिशा

गुड़गांव टुडे, गुरुग्राम

लेजर वैली मैदान में आयोजित 71वें राज्य स्तरीय सहकारिता समापन समारोह ने सहकारिता की भावना और सामुदायिक विकास के महत्व को एक नई दिशा दी। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी और सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा के साथ गुड़गांव के विधायक मुकेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया।

समारोह में प्रदेश की सहकारी समितियों और उनके पदाधिकारियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इन समितियों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से न केवल आर्थिक सशक्तिकरण किया है, बल्कि सामूहिक प्रयासों से आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अग्रसर किया है।

मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सैनीने अपने संबोधन में कहा, सहकारिता का यह मंच हमें एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा देता है। सहकारिता की भावना से ही हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार कर सकते हैं। गुरुग्राम जैसे शहरों में सहकारी संस्थानों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, जहां तेज आर्थिक विकास की संभावनाएं हैं।

समारोह में सहकारिता के क्षेत्र में नई पहल और उपलब्धियों की जानकारी दी गई। सहकारी संस्थानों की सफलता के अनुभव साझा किए गए। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति से समारोह को गरिमामयी बनाया।

आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम : मुकेश शर्मा

इस समारोह के समापन के बाद मीडिया को दिए अपने संबोधन में विधायक मुकेश शर्मा ने सहकारिता के क्षेत्र में हरियाणा सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, सहकारिता न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है। हमारी सरकार इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधायक ने सहकारिता के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को सशक्त करने की बात कही। उन्होंने सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बताते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आधार बताया।

विकास के लिए सहकारिता समितियों से जुड़ें लोग : मुख्यमंत्री

लेजर वैली पार्क में 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह का किया गया आयोजन

50 करोड़ की लागत से 658 गांवों में श्मशान घाट और कब्रिस्तान दोबारा बनेंगे

प्रैस कतरनें

दूध के उत्पादों की दूसरे राज्यों में डिमांड, फिर से गति पकड़ेंगी योजनाएं: सहकारिता मंत्री

हर गांव में पैक्स स्थापित करने का है सरकार का मुख्य लक्ष्य

इन उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी

21 नवंबर को समापन समारोह में मुख्यमंत्री होंगे मुख्य अतिथि

अपने संबोधन के दौरान सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 71वें सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम के समापन के अवसर पर गुरुग्राम में 21 नवंबर को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह मुख्य अतिथि होंगे।

सहकारिता से जुड़कर आत्मनिर्भर बनें : राजेश जोगपाल

पहले गुलाबी गैंग कहते थे, अब किलकारी गैंग हो गया : डा. अरविंद शर्मा

खराबी की बात घुस गई, जो अगले बीस वर्ष तक जाने वाली नहीं है। प्रदेश में खाद की कमी के सवाल पर अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दो घंटे 40 मिनट भाषण दिया। जिसमें उन्होंने प्रदेश में कोई खाद की कमी नहीं बताई। किसी भी जिले में कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में डीएपी है।

सभी जिला मुख्यालयों पर विशेष कैंप लगाकर दी जाएगी लोगों को सहकारी योजनाओं की जानकारी: मंत्री

प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र को किया जाएगा विकसित

प्रदेश स्तरीय सहकारिता सप्ताह समारोह के दौरान सहकारी संघों द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई

हरिभूमि न्यूज़ | रोहतक

रोहतक। आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह का दीप जलाकर शुभारंभ करते सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा। फोटो: हरिभूमि

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की नीतियों से सहकारिता क्षेत्र ने नए आयाम स्थापित किए

रोहतक। आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह को सम्बोधित करते सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा। फोटो: हरिभूमि

प्रदेश की 33 हजार समितियों से जुड़े हैं 55 लाख लोग

हर गांव में पैक्स स्थापित करने का है मुख्य लक्ष्य

ये रहे मौजूद

Agri credit societies to be set up in each village: Minister

RAVINDER SAINI
TRIBUNE NEWS SERVICE

ROHTAK, NOVEMBER 15

Cooperation, Tourism and Jail Minister Dr Arvind Sharma has said the state government's aim was to establish primary agricultural credit societies (PACS) in every village so as to connect more and more people with it.

Addressing a state-level function at Maharshi Dayanand University (MDU) here, Sharma said: "The state government is determined to realise the dream of PM Narendra Modi by involving more and more people in the field of cooperation. For this, special camps will be organised in every district headquarters in the coming time, through which people will be informed about cooperation schemes so that they can become self-reliant by forming their groups."

Cooperation Minister Dr Arvind Sharma in Rohtak. DEVENDER SHARMA

The minister pointed out that there were immense possibilities of becoming self-reliant by adopting cooperation. The cooperative sector of the state would be developed on the lines of Gujarat and Maharashtra. "The state government is implementing many schemes to promote cooperation to ensure direct benefit to those associated with the cooperation sector. Till a few years ago, there was a demand for Haryana's milk products in other states but some stagnation came in between. Now, the time has come to give it a momentum again. HAFED's products are being exported to Dubai and Abu Dhabi," said Sharma.

The minister instructed all officers of the Cooperative Department to work in such an effective manner that there is an increase of 20 to 25 per cent in the co-operative sector. "At present, 55 lakh people are associated with 33,000 cooperative committees of the state. All these people do their work by forming groups. By forming small groups, citizens can join the cooperative sector and set up petrol pumps, gas agencies and warehouses. For this, loans are being provided by the government at cheap interest rates," Sharma added.

लोगों को देंगे सहकारिता योजनाओं की जानकारी: डॉ. अरविंद शर्मा

प्रदेश स्तरीय सहकारिता सप्ताह समारोह शुरू

रोहतक | सहकारिता मंत्री को स्मृति चिह्न भेंट करते हुए अधिकारी।

भास्कर न्यूज़ | रोहतक

प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि जिला मुख्यालयों पर विशेष कैंप से सहकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सहकारिता के क्षेत्र में अधिक लोगों की भागीदारी कर पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के सपने को साकार करना है। जल्द हर जिला मुख्यालय पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से लोगों को सहकारिता की जानकारी दी जाएगी। ताकि वे अपने ग्रुप बनाकर सहकारिता से जुड़कर स्वावलंबी बन सकें।

वे शुक्रवार को एमडीयू के टैगोर सभागार में प्रदेश स्तरीय 71वें सहकारिता सप्ताह समारोह का शुभारंभ कर रहे थे। इस दौरान सहकारी संघ, सहकारी समितियों और महिला स्वयं सहायता समूहों ने स्टॉल लगाकर लोगों को उत्पादों व योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहकारिता को अपनाकर आत्मनिर्भर बनने की अपार संभावनाएं हैं। भविष्य में सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र को गुजरात व महाराष्ट्र की तर्ज पर विकसित करना है। उन्होंने किसानों, आमजन से आह्वान किया कि वे सहकारिता क्षेत्र से जुड़ें। नौकरी के पीछे भागने की बजाय नौकरी देने वाले बनें।

हर गांव में बनेंगे पैक्स

मंत्री ने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर गांव में पैक्स स्थापित हों व अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ें। सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम के समापन पर गुरुग्राम में 21 नवंबर को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा। सीएम नायब सिंह मुख्य अतिथि होंगे।

मंत्री अरविंद शर्मा ने 71वें सहकारिता सप्ताह समारोह को किया संबोधित, कहा

जिला मुख्यालयों पर विशेष कैंप लगाकर दी जाएगी योजनाओं की जानकारी

रोहतक, 15 नवंबर (हप्र)

प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के सपने को साकार करना है। इसके लिए आने वाले समय में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से लोगों को सहकारिता की जानकारी दी जाएगी ताकि वे अपने ग्रुप बनाकर सहकारिता से जुड़कर स्वावलंबी बन सकें। उन्होंने कहा कि सहकारिता को अपनाकर आत्मनिर्भर बनने की अपार संभावनाएं हैं। आने वाले समय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र को गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर विकसित करना है।

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा शुक्रवार को 71वें सहकारिता सप्ताह के तहत स्थानीय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय स्थित टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में पैक्स स्थापित हो और अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ें। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग का लक्ष्य एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 मानकर काम करना है। शर्मा ने बताया कि 71 वें सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम के समापन के अवसर पर गुरुग्राम में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर तरक्की कर रहा है और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की बहुत ही कारगर नीतियों की बदौलत सहकारिता क्षेत्र नए आयाम स्थापित कर रहा है।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि कुछ साल पहले तक हरियाणा के दूध के उत्पादों की मांग दूसरे प्रदेशों में थी। उन्होंने कहा कि दुबई और आबू धाबी में भी हैफेड के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने समारोह में उपस्थित सहकारिता विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे ऐसे प्रभावशाली ढंग से कार्य करें जिससे कि चंद ही दिनों में सहकारिता क्षेत्र में 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार राजेश जोगपाल ने कहा कि सहकारिता विभाग किसानों के साथ-साथ आमजन को खुशहाल बनाने का काम कर रहा है। प्रदेश में सहकारिता के विजन को साकार किया जा रहा है।

सहकारिता सप्ताह समारोह को हरकोफेड के चेयरमैन वेदफूला, शुगरफेड के चेयरमैन धर्मवीर डागर, मार्केटिंग बैंक के चेयरमैन अमरपाल राणा, हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी ने भी अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से जानकारी दी। हरकोफैड की प्रबंध निदेशक सुमन बल्हारा ने आभार प्रकट किया। समारोह में सहकारिता के क्षेत्र में कार्यों पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। समारोह के दौरान सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया।

प्रदर्शनी में हैफेड ने तेल, चावल, चीनी, घी, चीटा का उत्पाद, सहकारी चीनी मिल द्वारा चीनी, गन्ना उत्पादन, बैंकिंग प्रणाली ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, पंचकूला से सहकारिता विभाग द्वारा ट्रैक्टर के नमूने, हरको हेड द्वारा जूट बैग, पानीपत द्वारा गर्म कंबल और बेडशीट, केंद्रीय सहकारी बैंक रोहतक द्वारा शहद और महिलाओं के श्रृंगार का सामान, सुमाखेड़ा रेवाड़ी द्वारा पीतल के बर्तन और बैग, सोनीपत द्वारा अचार के उत्पाद, सिरसा द्वारा शीशम, तुलसी, बेरी के शहद के उत्पादन, यमुनानगर द्वारा फ्रूट के उत्पाद, दी हरियाणा स्टेट सीएम पैक्स एलटीएम द्वारा कृषि यंत्र का प्रदर्शन किया गया।

रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय स्थित टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह का शुभारंभ करते सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा। -हप्र

समारोह में ये रहे मुख्य रूप से मौजूद

प्रदेश स्तरीय सहकारी सप्ताह समारोह के दौरान डीसी धीरेंद्र खड़गटा, शुगरफेड के एमडी कैप्टन शक्ति सिंह, एडीसी नरेंद्र कुमार, एसडीएम आशीष कुमार, शुगर मिल रोहतक की एमडी मेजर गायत्री अहलावत, भाजपा जिलाध्यक्ष रणबीर ढाका, संयुक्त रजिस्ट्रार हरप्रीत कौर, शुगर मिल पलवल के एमडी विशाल, शुगर मिल कैथल के एमडी कृष्ण कुमार, हाउस फैड के एमडी योगेश शर्मा, श्रम एवं निर्माण के एमडी वीरेंद्र दहिया, डेयरी फैड के एमडी रोहित यादव, हरको बैंक के एमडी प्रफुल रंजन, अतिरिक्त रजिस्ट्रार कवित धनखड़, डिप्टी रजिस्ट्रार सरिता राठी सहित विभाग के अनेक अधिकारियों के अलावा पूर्व डिप्टी मेयर राजकमल सहगल, नरेंद्र खट्टर, नरेंद्र वत्स, गुलशन दुआ, हरिओम तिवारी सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

दुबई और आबू धाबी में भी हैफेड के प्रोडक्ट को किया जा रहा एक्सपोर्ट : अरविंद शर्मा

मदवि के टैगोर सभागार में आयोजित समारोह में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे सहकारिता मंत्री

रोहतक,15 नवम्बर (मैनपाल): प्रदेश के सहकारिता मंत्री डा. अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि कुछ साल पहले तक हरियाणा के दूध के उत्पादों की मांग दूसरे प्रदेशों में थी। लेकिन बीच में उन पर कुछ ठहराव सा लगा, अब उनको अब उनको फिर से गति प्रदान करनी है।

उन्होंने कहा कि दुबई और आबू धाबी में भी हैफेड के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बता दें कि सहकारिता मंत्री डा. अरविंद शर्मा शुक्रवार को 71वें सहकारिता सप्ताह के तहत स्थानीय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय स्थित टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह को बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए नहीं-नहीं योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ सहकारिता से क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिल रहा है।

उन्होंने सभागार में उपस्थित किसानों व आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि वे सहकारिता क्षेत्र से जुड़ें। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में आकर नौकरी के पीछे भागने की बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे।

उन्होंने समारोह में उपस्थित सहकारिता विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे ऐसे प्रभावशाली ढंग से कार्य करें जिससे कि चंद ही दिनों में सहकारिता क्षेत्र में 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो। प्रदेश स्तरीय सहकारी सप्ताह समारोह के दौरान डी.सी. धीरेंद्र खड़गटा, शुगरफेड के एम.डी. कैप्टन शक्ति सिंह, ए.डी.सी. नरेंद्र कुमार, एस.डी.एम. आशीष कुमार, शुगर मिल रोहतक की एम.डी. मेजर गायत्री अहलावत, भाजपा जिलाध्यक्ष रणबीर ढाका, संयुक्त रजिस्ट्रार हरप्रीत कौर, शुगर मिल पलवल के एमडी विशाल, शुगर मिल कैथल के एमडी कृष्ण कुमार, हाऊस फैड के एमडी योगेश शर्मा, श्रम एवं निर्माण के एमडी वीरेंद्र दहिया, डेयरी फैड के एमडी रोहित यादव, हरको बैंक के एमडी प्रफुल रंजन, अतिरिक्त रजिस्ट्रार कवित धनखड़, डिप्टी रजिस्ट्रार सरिता राठी सहित विभाग के अनेक अधिकारियों के अलावा पूर्व डिप्टी मेयर राजकमल सहगल, नरेंद्र खट्टर, नरेंद्र वत्स, गुलशन दुआ, हरिओम तिवारी सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते डा. अरविंद शर्मा व मंच पर बैग भेंट करते डा. शर्मा।

विशेष कैंप लगाकर दी जाएगी योजनाओं जानकारी

डा. अरविंद शर्मा ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के सपने को साकार करना है। इसके लिए आने वाले समय में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से लोगों को सहकारिता की जानकारी दी जाएगी ताकि वे अपने ग्रुप बनाकर सहकारिता से जुड़कर स्वावलंबी बन सकें।

प्रदेश की 33 हजार समितियां से जुड़े हैं करीब 55 लाख लोग :

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री डा. शर्मा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में करीब 33000 सरकारी समितियां हैं जिससे युवा, बुजुर्ग और महिलाओं सहित करीब 55 लाख सदस्य जुड़े हुए हैं।

ये सभी लोग समूह बनाकर अपना काम करते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे समूह बनाकर नागरिक सहकारिता क्षेत्र से जुड़कर पैट्रोल पंप, गैस एजेंसी और वेयरहाऊस तक स्थापित कर सकते हैं।

इसके लिए सरकार द्वारा सस्ती ब्याजदरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विशेष कैंप लगाकर दी जाएगी लोगों को सहकारी योजनाओं की जानकारी :- सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा

अधिक से अधिक भागीदारी कर भारत को विकसित बनाने के सपने को साकार करना है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में प्रदेश स्तरीय 71वें सहकारिता सप्ताह समारोह को किया बतौर मुख्य अतिथि संबोधित। सहकारी संघ, सहकारी समितियों व महिला स्वयं सहायता द्वारा स्टॉल लगाकर दी गई अपने उत्पादों व योजनाओं की जानकारी। समारोह के दौरान ढोल नगाड़ों के साथ हुआ सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा का स्वागत

प्रैस कतरनें

कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री ने किया प्राथमिक सहकारी समितियों को लाभ में लाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान

विदेशों में धूम मचाएंगे सहकारिता संस्थाओं के उत्पाद : डॉ. अरविंद शर्मा

➡ भारतीय सेना, मलेशिया व इंडोनेशिया में वीटा का दूध, दुबई व अबू धाबी में हैफेड उत्पाद हो रहे हैं निर्यात

जयमार्ग न्यूज

गोहाना। सहकारिता, कारागार, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का संकल्प हर घर में सहकारिता का लाभ पहुंचाना है।

इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सहकारिता विभाग प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को लाभ में लाने के लिए कमर कस चुका है। हम सब मिलकर युवाओं, विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे और उनको रोजगार पाने की बजाय रोजगार देने वाले बनाने का काम करेंगे। वीरवार को सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने प्रदेश भर में सहकार से समृद्धि के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए गोहाना में जिला स्तरीय सहकारिता जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात की तर्ज पर हरियाणा में प्राथमिक सहकारी समितियों को लाभ में लाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि किसान, महिला से लेकर युवा तक सहकारी संस्थाओं व हर योजना की जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि वो तय कर सकें कि किस योजना में वो आत्मनिर्भर बनते हुए देश, समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें रोजगार पाने की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाते हुए रोजगार देने की सोच को मजबूत करना है। कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि सहकारी संस्थाओं के उत्पाद सेना से लेकर विदेशों में दुबई और अबू धाबी तक अपनी धूम मचा रहे हैं और हम सभी मिलकर सहकारी उत्पादों को विदेशों में बढ़ावा देंगे, ताकि हमारी सहकारी समितियों से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को समय पर लोन चुकाना और बेहतर विपणन प्रणाली के माध्यम से मुनाफे में लाने के लिए मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग विचार कर रहा है कि जो युवा निजी स्थान पर सहकारी संस्थाओं के उत्पादों को बिक्री करते हुए अपना काम शुरू करें, ताकि उनका स्वरोजगार विकसित हो। कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने सोनीपत सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा शुरू की गई तीन योजनाओं म्हारे बुजुर्ग-म्हारी धरोहर, वीरांगना लक्ष्मीबाई बचत योजना व नारी शक्ति उत्थान योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य सहकारी बैंक व जिला सहकारी बैंक की स्वंय सहायता समूहों के लिए संयुक्त योजना में 208 समूहों को 4 करोड़ 16 लाख रुपए का लोन चेक वितरित किए। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने जनमानस को ... कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने जागरूकता अभियान को शनिवार तक जारी रखने के आदेश दिए। इस अवसर पर गन्नौर विधायक देवेंद्र कादयान, कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा की धर्मपत्नी डॉ. रीटा शर्मा, सहकारी संस्थानों के चेयरमैन धर्मबीर डागर, अमरपाल राणा व हुकम सिंह भाटी, हरियाणा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार राजेश जोगपाल, हैफेड एमडी मुकुल कुमार, हरकोफेड एमडी सुमन बलहारा, संयुक्त रजिस्ट्रार हरप्रीत कौर, नरेश गोयल व योगेश शर्मा, गौकर्ण धाम के प्रमुख महंत बाबा कपिल पुरी महाराज आदि मौजूद थे।

... Postal Regd KKR/174/2024-2026

Work together to bring co-op societies into profit: Minister

MUKESH TANDON
TRIBUNE NEWS SERVICE

SONEPAT, DECEMBER 26

Co-operations, Prison, Heritage and Tourism Minister Dr Arvind Sharma on Thursday gave a call to work together to bring primary cooperative societies into profit. He announced that plans would be implemented to set up government co-operative product Vita produce sales centres at private places.

The Co-operations Minister Dr Arvind Sharma was addressing the gathering after inaugurating the district-level co-operative awareness campaign in Gohana on Thursday. The Co-operatives Department had geared up to bring primary agricultural cooperative societies into profit, he said. "We will make the youth, especially women, self-reliant and will work to make them job providers instead of job seekers," he added.

The minister said a special action plan was being prepared to bring primary co-operative societies in the state into profit on the lines of Karnataka, Maharashtra and Gujarat.

"Our goal is to provide information about every scheme of co-operative societies to farmers, women and youth, so that they can decide in which scheme they can become self-reliant," the minister added.

Dr Sharma said the products of co-operative societies were being sold in the Army cantts and abroad in Dubai and Abu Dhabi.

He said that co-operative societies had to repay loans on time and work together to bring them into profit through better marketing system. "The Co-operative Department is considering that the youth should start their own work by selling the products of co-operative institutions at private places so that they can generate self-employment," he asserted.

Sharma inaugurated three schemes, which were launched by Sonipat Central Cooperative Bank Limited, 'mhare bujurg-mhari dharohar', 'veerangana Laxmibai bachat yojana' and 'nari shakti utthan yojana'.

Overwhelmed with the crowd, the Cabinet Minister directed to continue the awareness campaign in Gohana till Saturday.

Co-operations Minister Dr Arvind Sharma inaugurates the awareness programme at Gohana.

सेना, मलेशिया और इंडोनेशिया में निर्यात कर रहे वीटा का दूध : डॉ. शर्मा

युवाओं के लिए वीटा उत्पाद बिक्री केंद्र स्थापित करने की योजना बनाएंगे

■ हम सब मिलकर युवाओं विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे

हरिभूमि न्यूज ▶▶ गोहाना

सहकारिता, कारागार, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का संकल्प हर घर में सहकारिता का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सहकारिता विभाग प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को लाभ में लाने के लिए कमर कस चुका है। हम सब मिलकर युवाओं, विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे और उनको रोजगार पाने की बजाय रोजगार देने वाले बनाने का काम करेंगे। वीरवार को सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने प्रदेश भर में सहकार से समृद्धि के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए गोहाना में जिला स्तरीय सहकारिता जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात की तर्ज पर हरियाणा में प्राथमिक सहकारी समितियों को लाभ में लाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि किसान, महिला से लेकर युवा तक सहकारी संस्थाओं हर योजना की जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि वो तय कर सकें कि किस योजना में वो आत्मनिर्भर बनते हुए देश, समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें रोजगार पाने की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाते हुए रोजगार देने की सोच को मजबूत करना है। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि सहकारी संस्थाओं के उत्पाद सेना से लेकर विदेशों में दुबई और आबु धाबी तक अपनी धूम मचा रहे हैं और हम सभी मिलकर सहकारी उत्पादों को विदेशों में बढ़ावा देंगे, ताकि हमारी सहकारी समितियों से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को समय पर लोन चुकाना और बेहतर विपणन प्रणाली के माध्यम से मुनाफे में लाने के लिए मिलकर काम करना है। सहकारिता विभाग विचार कर रहा है कि जो युवा निजी स्थान पर सहकारी संस्थाओं के उत्पादों को बिक्री करते हुए अपना काम शुरू करें, ताकि उनका स्वरोजगार विकसित हो।

गोहाना। पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा। फोटो : हरिभूमि

तीन योजनाओं का शुभारंभ किया

कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने सोनीपत सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा शुरू की गई तीन योजनाओं म्हारे बुजुर्ग-म्हारी धरोहर, वीरांगना लक्ष्मीबाई बचत योजना व नारी शक्ति उत्थान योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य सहकारी बैंक व जिला सहकारी बैंक की स्वंय सहायता समूहों के लिए संयुक्त योजना में 208 समूहों को 4 करोड़ 16 लाख रूपए का लोन चैक वितरित किए। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

इस अवसर पर गन्नौर विधायक देवेन्द्र कादयान, कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा की धर्मपत्नी डॉ. रीटा शर्मा, सहकारी संस्थानों के चेयरमैन धर्मबीर डागर, अमरपाल राणा व हुकुम सिंह भाटी, हरियाणा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार राजेश जोगपाल, हैफेड एमडी मुकुल कुमार, हरकोफेड एमडी सुमन बल्हारा, संयुक्त रजिस्ट्रार हरप्रीत कौर, नरेश गोयल व योगेश शर्मा, गौकर्ण धाम के प्रमुख महंत बाबा कमल पुरी महाराज, अतिरिक्त रजिस्ट्रार कविता धनखड़ व वीरेंद्र दहिया, एसडीएम गोहाना अंजलि श्रोत्रिय, एमडी शुगर मिल अंकिता वर्मा, पूर्व महापौर मनमोहन गोयल व रेणु डाबला, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष बलराम कौशिक आदि उपस्थित रहे।

सहकारिता जागरूकता अभियान के दूसरे दिन बारिश में भी पहुंची जनता

गोहाना, 27 दिसम्बर (अरोड़ा): सहकारिता विभाग द्वारा शहर में संचालित जिला स्तरीय सहकारिता जागरूकता अभियान के दूसरे दिन शुक्रवार को बारिश के बीच भी जनता ने भागीदारी की। विभिन्न स्टालों पर योजनाओं और उत्पादों की जानकारी लेने के साथ-साथ लोगों ने सोसायटी पंजीकरण की प्रक्रिया करवाई।

गुरुवार को सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने चौ. देवीलाल स्टेडियम में जिला स्तरीय सहकारिता जागरूकता अभियान की मुहिम का शुभारंभ करते हुए प्रदर्शनी को शनिवार तक बढ़ाने की घोषणा की थी। शुक्रवार को सुबह से ही हो रही बारिश के बाद भी स्टेडियम परिसर में आमजन का आवागमन लगा रहा। जिला स्तरीय सहकारिता जागरूकता अभियान के नोडल अधिकारी सतीश रोहिल्ला की अगुवाई में विभिन्न स्टालों पर आमजन को जानकारी प्रदान की गई।

अधिकारी एक आवेदक को पंजीकरण का प्रमाणपत्र देते हुए। (अरोड़ा)

रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के स्टॉल पर सहायक रजिस्ट्रार प्रशांत शर्मा के सामने 10 सोसायटी पंजीकरण को लेकर अलग-अलग गांवों से लोग पहुंचे। उन्हें सोसायटी पंजीकरण की प्रक्रिया और दस्तावेज की जानकारी उपलब्ध करवाई गई।

सोनीपत केंद्रीय सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक महताब सिंह ने बताया कि सहकारी बैंक अन्य बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। उन्होंने म्हारे बुजुर्ग-म्हारी धरोहर, वीरांगना लक्ष्मीबाई बचत योजना व नारी शक्ति उत्थान योजना की जानकारी दी। डेयरीफैड के वीटा स्टाल पर डेयरी सहकारी समिति पंजीकरण, दूध संकलन केंद्र के तौर पर स्वरोजगार की सम्भावना पर विस्तार से जानकारी दी गई।

इसी प्रकार हैफेड अधिकारियों द्वारा भी उत्पादों की जानकारी दी गई, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक व अन्य उत्पाद के बारे में बताया गया। हरको बैंक के स्टाल पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को दिए जा रहे ऋण की जानकारी दी गई। शूगर मिल स्टॉल पर गन्ना बिजाई को बढ़ावा देने व सरकार द्वारा फसल के सबसे ज्यादा रेट व समय पर भुगतान की जानकारी सांझा की गई।

जागरूकता अभियान के नोडल अधिकारी सतीश रोहिल्ला ने बताया कि यदि शनिवार को भी बारिश रही तो प्रदर्शनी स्टेडियम परिसर के हाल में लगाई जाएगी।

हरकोफैड 2025

विक्रमी संवत् - 2081-82

जनवरी — पौष–माघ

रवि	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि
			1 शु.द्वितीया	2 शु.तृतीया	3 शु.चतुर्थी	4 शु.पंचमी
5 शु.षष्ठी	6 शु.सप्तमी	7 शु.अष्टमी	8 शु.नवमी	9 शु.दशमी	10 शु.एकादशी	11 शु.द्वादशी/त्रयोदशी
12 शु.चतुर्दशी	13 पौष पूर्णिमा	14 माघ कृ.प्रतिपदा	15 कृ.द्वितीया	16 कृ.तृतीया	17 कृ.चतुर्थी	18 कृ.पंचमी
19 कृ.पंचमी	20 कृ.षष्ठी	21 कृ.सप्तमी	22 कृ.अष्टमी	23 कृ.नवमी	24 कृ.दशमी	25 कृ.एकादशी
26 कृ.द्वादशी	27 कृ.त्रयोदशी	28 कृ.चतुर्दशी	29 माघ अमावस्या	30 माघ शु.प्रतिपदा	31 शु.द्वितीया	

फरवरी — माघ–फाल्गुन

रवि	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि
						1 शु.तृतीया
2 शु.चतुर्थी/पंचमी	3 शु.षष्ठी	4 शु.सप्तमी	5 शु.अष्टमी	6 शु.नवमी	7 शु.दशमी	8 शु.एकादशी
9 शु.द्वादशी	10 शु.त्रयोदशी	11 शु.चतुर्दशी	12 माघ पूर्णिमा	13 फाल्गुन कृ.प्रतिपदा	14 कृ.द्वितीया	15 कृ.तृतीया
16 कृ.चतुर्थी	17 कृ.पंचमी	18 कृ.षष्ठी	19 कृ.षष्ठी	20 कृ.सप्तमी	21 कृ.अष्टमी	22 कृ.नवमी
23 कृ.दशमी	24 कृ.एकादशी	25 कृ.द्वादशी	26 कृ.त्रयोदशी	27 कृ.चतुर्दशी/फाल्गुन अमावस्या	28 फाल्गुन शु.प्रतिपदा	

मार्च — फाल्गुन–चैत्र

रवि	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि
30 चैत्र शु.प्रतिपदा	31 शु.द्वितीया/तृतीया					1 शु.द्वितीया
2 शु.तृतीया	3 शु.चतुर्थी	4 शु.पंचमी	5 शु.षष्ठी	6 शु.सप्तमी	7 शु.अष्टमी	8 शु.नवमी
9 शु.दशमी	10 शु.एकादशी	11 शु.द्वादशी	12 शु.त्रयोदशी	13 शु.चतुर्दशी	14 फाल्गुन पूर्णिमा	15 चैत्र कृ.प्रतिपदा
16 कृ.द्वितीया	17 कृ.तृतीया	18 कृ.चतुर्थी	19 कृ.पंचमी	20 कृ.षष्ठी	21 कृ.सप्तमी	22 कृ.अष्टमी
23 कृ.नवमी	24 कृ.दशमी	25 कृ.एकादशी	26 कृ.द्वादशी	27 कृ.त्रयोदशी	28 कृ.चतुर्दशी	29 चैत्र अमावस्या

अप्रैल — चैत्र – वैशाख

रवि	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि
		1 शु.चतुर्थी	2 शु.पंचमी	3 शु.षष्ठी	4 शु.सप्तमी	5 शु.अष्टमी
6 शु.नवमी	7 शु.दशमी	8 शु.एकादशी	9 शु.द्वादशी	10 शु.त्रयोदशी	11 शु.चतुर्दशी	12 चैत्र पूर्णिमा
13 वैशाख कृ.प्रतिपदा	14 कृ.प्रतिपदा	15 कृ.द्वितीया	16 कृ.तृतीया	17 कृ.चतुर्थी	18 कृ.पंचमी	19 कृ.षष्ठी
20 कृ.सप्तमी	21 कृ.अष्टमी	22 कृ.नवमी	23 कृ.दशमी	24 कृ.एकादशी	25 कृ.द्वादशी	26 कृ.त्रयोदशी/चतुर्दशी
27 वैशाख अमावस्या	28 वैशाख शु.प्रतिपदा	29 शु.द्वितीया	30 शु.तृतीया			

मई — वैशाख–ज्येष्ठ

रवि	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि
				1 शु.चतुर्थी	2 शु.पंचमी	3 शु.षष्ठी
4 शु.सप्तमी	5 शु.अष्टमी	6 शु.नवमी	7 शु.दशमी	8 शु.एकादशी	9 शु.द्वादशी	10 शु.त्रयोदशी
11 शु.चतुर्दशी	12 वैशाख पूर्णिमा	13 ज्येष्ठ कृ.प्रतिपदा	14 कृ.द्वितीया	15 कृ.तृतीया	16 कृ.चतुर्थी	17 कृ.पंचमी
18 कृ.पंचमी	19 कृ.षष्ठी	20 कृ.सप्तमी/अष्टमी	21 कृ.नवमी	22 कृ.दशमी	23 कृ.एकादशी	24 कृ.द्वादशी
25 कृ.त्रयोदशी	26 कृ.चतुर्दशी	27 ज्येष्ठ अमावस्या/शु.प्रतिपदा	28 शु.द्वितीया	29 शु.तृतीया	30 शु.चतुर्थी	31 शु.पंचमी

जून — ज्येष्ठ–आषाढ़

रवि	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि
1 शु.षष्ठी	2 शु.सप्तमी	3 शु.अष्टमी	4 शु.नवमी	5 शु.दशमी	6 शु.एकादशी	7 शु.द्वादशी
8 शु.द्वादशी	9 शु.त्रयोदशी	10 शु.चतुर्दशी	11 ज्येष्ठ पूर्णिमा	12 आषाढ़ कृ.प्रतिपदा	13 कृ.द्वितीया	14 कृ.तृतीया
15 कृ.चतुर्थी	16 कृ.पंचमी	17 कृ.षष्ठी	18 कृ.सप्तमी	19 कृ.अष्टमी	20 कृ.नवमी	21 कृ.दशमी/एकादशी
22 कृ.द्वादशी	23 कृ.त्रयोदशी	24 कृ.चतुर्दशी	25 आषाढ़ अमावस्या	26 शु.प्रतिपदा	27 शु.द्वितीया	28 शु.तृतीया
29 शु.चतुर्थी	30 शु.पंचमी					

जुलाई — आषाढ़–श्रावण

रवि	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि
		1 शु.षष्ठी	2 शु.सप्तमी	3 शु.अष्टमी	4 शु.नवमी	5 शु.दशमी
6 शु.एकादशी	7 शु.द्वादशी	8 शु.त्रयोदशी	9 शु.चतुर्दशी	10 आषाढ़ पूर्णिमा	11 श्रावण कृ.प्रतिपदा	12 कृ.द्वितीया
13 कृ.तृतीया	14 कृ.चतुर्थी	15 कृ.पंचमी	16 कृ.षष्ठी	17 कृ.सप्तमी	18 कृ.अष्टमी	19 कृ.नवमी
20 कृ.दशमी	21 कृ.एकादशी	22 कृ.द्वादशी/त्रयोदशी	23 कृ.चतुर्दशी	24 श्रावण अमावस्या	25 श्रावण शु.प्रतिपदा	26 शु.द्वितीया
27 शु.तृतीया	28 शु.चतुर्थी	29 शु.पंचमी	30 शु.षष्ठी	31 शु.सप्तमी		

अगस्त — श्रावण–भाद्रपद

रवि	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि
31 शु.अष्टमी					1 शु.अष्टमी	2 शु.अष्टमी
3 शु.नवमी	4 शु.दशमी	5 शु.एकादशी	6 शु.द्वादशी	7 शु.त्रयोदशी	8 शु.चतुर्दशी	9 श्रावण पूर्णिमा
10 भाद्रपद कृ.प्रतिपदा	11 कृ.द्वितीया	12 कृ.तृतीया	13 कृ.चतुर्थी/पंचमी	14 कृ.षष्ठी	15 कृ.सप्तमी	16 कृ.अष्टमी
17 कृ.नवमी	18 कृ.दशमी	19 कृ.एकादशी	20 कृ.द्वादशी	21 कृ.त्रयोदशी	22 कृ.चतुर्दशी	23 भाद्रपद अमावस्या
24 भाद्रपद शु.प्रतिपदा	25 शु.द्वितीया	26 शु.तृतीया	27 शु.चतुर्थी	28 शु.पंचमी	29 शु.षष्ठी	30 शु.सप्तमी

सितम्बर — भाद्रपद–आश्विन

रवि	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि
	1 शु.नवमी	2 शु.दशमी	3 शु.एकादशी	4 शु.द्वादशी	5 शु.त्रयोदशी	6 शु.चतुर्दशी
7 भाद्रपद पूर्णिमा	8 आश्विन कृ.प्रतिपदा	9 कृ.द्वितीया	10 कृ.तृतीया	11 कृ.चतुर्थी	12 कृ.पंचमी	13 कृ.षष्ठी/सप्तमी
14 कृ.अष्टमी	15 कृ.नवमी	16 कृ.दशमी	17 कृ.एकादशी	18 कृ.द्वादशी	19 कृ.त्रयोदशी	20 कृ.चतुर्दशी
21 आश्विन अमावस्या	22 आश्विन शु.प्रतिपदा	23 शु.द्वितीया	24 शु.तृतीया	25 शु.तृतीया	26 शु.चतुर्थी	27 शु.पंचमी
28 शु.षष्ठी	29 शु.सप्तमी	30 शु.अष्टमी				

अक्तूबर — आश्विन–कार्तिक

रवि	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि
			1 शु.नवमी	2 शु.दशमी	3 शु.एकादशी	4 शु.द्वादशी
5 शु.त्रयोदशी	6 शु.चतुर्दशी	7 आश्विन पूर्णिमा/कार्तिक कृ.प्रतिपदा	8 कृ.द्वितीया	9 कृ.तृतीया	10 कृ.चतुर्थी	11 कृ.पंचमी
12 कृ.षष्ठी	13 कृ.सप्तमी	14 कृ.अष्टमी	15 कृ.नवमी	16 कृ.दशमी	17 कृ.एकादशी	18 कृ.द्वादशी
19 कृ.त्रयोदशी	20 कृ.चतुर्दशी	21 कार्तिक अमावस्या	22 कार्तिक शु.प्रतिपदा	23 शु.द्वितीया	24 शु.तृतीया	25 शु.चतुर्थी
26 शु.पंचमी	27 शु.षष्ठी	28 शु.षष्ठी	29 शु.सप्तमी	30 शु.अष्टमी	31 शु.नवमी	

नवम्बर — कार्तिक–मार्गशीर्ष

रवि	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि
30 शु.दशमी						1 शु.दशमी
2 शु.एकादशी/द्वादशी	3 शु.त्रयोदशी	4 शु.चतुर्दशी	5 कार्तिक पूर्णिमा	6 मार्गशीर्ष कृ.प्रतिपदा	7 कृ.द्वितीया	8 कृ.तृतीया/चतुर्थी
9 कृ.पंचमी	10 कृ.षष्ठी	11 कृ.सप्तमी	12 कृ.अष्टमी	13 कृ.नवमी	14 कृ.दशमी	15 कृ.एकादशी
16 कृ.द्वादशी	17 कृ.त्रयोदशी	18 कृ.त्रयोदशी	19 कृ.चतुर्दशी	20 मार्गशीर्ष अमावस्या	21 मार्गशीर्ष शु.प्रतिपदा	22 शु.द्वितीया
23 शु.तृतीया	24 शु.चतुर्थी	25 शु.पंचमी	26 शु.षष्ठी	27 शु.सप्तमी	28 शु.अष्टमी	29 शु.नवमी

दिसम्बर — मार्गशीर्ष–पौष

रवि	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि
	1 शु.एकादशी	2 शु.द्वादशी	3 शु.त्रयोदशी	4 शु.चतुर्दशी/मार्गशीर्ष पूर्णिमा	5 पौष कृ.प्रतिपदा	6 कृ.द्वितीया
7 कृ.तृतीया	8 कृ.चतुर्थी	9 कृ.पंचमी	10 कृ.षष्ठी	11 कृ.सप्तमी	12 कृ.अष्टमी	13 कृ.नवमी
14 कृ.दशमी	15 कृ.एकादशी	16 कृ.द्वादशी	17 कृ.त्रयोदशी	18 कृ.चतुर्दशी	19 पौष अमावस्या	20 पौष शु.प्रतिपदा
21 पौष शु.प्रतिपदा	22 शु.द्वितीया	23 शु.तृतीया	24 शु.चतुर्थी	25 शु.पंचमी	26 शु.षष्ठी	27 शु.सप्तमी
28 शु.अष्टमी	29 शु.नवमी	30 शु.दशमी/एकादशी	31 शु.द्वादशी			

अवकाश सूची

जनवरी	
सोमवार, 6	श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी जयंती
रविवार, 26	गणतन्त्र दिवस
फरवरी	
रविवार, 2	बसंत पंचमी/सर छोटू राम जयंती
बुधवार, 12	गुरु रविदास जयंती
रविवार, 23	महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती
बुधवार, 26	महाशिवरात्रि
मार्च	
शुक्रवार, 14	होली
रविवार, 23	शहीदी दिवस (भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव)
सोमवार, 31	ईद–उल–फितर
अप्रैल	
रविवार, 6	रामनवमी
वीरवार, 10	महावीर जयंती
रविवार, 13	वैसाखी/छठ पूजा
सोमवार, 14	डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती
शुक्रवार, 18	गुड फ्राइडे
मंगलवार, 29	परशुराम जयंती
बुधवार, 30	अक्षय तृतीया
मई	
सोमवार, 12	बुद्ध पूर्णिमा
शनिवार, 24	महर्षि कश्यप जयंती
वीरवार, 29	महाराणा प्रताप जयंती
शुक्रवार, 30	गुरु अर्जन देव शहीदी दिवस
जून	
शनिवार, 7	ईद–उल–जुहा (बकरीद)
बुधवार, 11	संत कबीर जयंती
जुलाई	
रविवार, 6	मुहर्रम
रविवार, 27	हरियाली तीज
वीरवार, 31	शहीद उधम सिंह शहीदी दिवस
अगस्त	
शनिवार, 9	रक्षा बंधन
शुक्रवार, 15	स्वतन्त्रता दिवस
शनिवार, 16	जन्माष्टमी
सितम्बर	
शुक्रवार, 5	मिलाद–उन–नबी/ईद–ए–मिलाद
सोमवार, 22	महाराजा अग्रसेन जयंती
मंगलवार, 23	शहीदी दिवस/हरियाणा वार हीरोज शहीदी दिवस
अक्तूबर	
वीरवार, 2	महात्मा गांधी जयंती/दशहरा
मंगलवार, 7	महर्षि वाल्मीकि जयंती/ महाराजा अजमीढ़ जयंती
शुक्रवार, 10	करवाचौथ
सोमवार, 20	दीपावली
बुधवार, 22	विश्वकर्मा दिवस/गोवर्धन पूजा
मंगलवार, 28	छठ पूजा
नवम्बर	
शनिवार, 1	हरियाणा दिवस
बुधवार, 5	गुरु नानक देव जयंती
मंगलवार, 25	गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस
दिसम्बर	
बुधवार, 24	गुरु ब्रह्मानन्द जयंती
वीरवार, 25	क्रिसमस दिवस
शुक्रवार, 26	शहीद उधम सिंह जयंती

विशिष्ट दिवसों की सूची

वीरवार, 23 जनवरी	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जयंती
बुधवार, 12 मार्च	संत लाधू नाथ जी जयंती
शनिवार, 15 मार्च	हसन खां मेवाती शहीदी दिवस
शुक्रवार, 11 अप्रैल	महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती
रविवार, 27 अप्रैल	संत धन्ना भगत जयंती
मंगलवार, 29 अप्रैल	श्री गुरु तेग बहादुर जी जयंती
शुक्रवार, 23 मई	श्री गुरु गोरक्षनाथ स्मृति दिवस
शनिवार, 31 मई	मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होल्कर जयंती
सोमवार, 9 जून	वीर बंदा बैरागी बलिदान दिवस
शुक्रवार, 4 जुलाई	भाई लखी शाह वंजारा जयंती
सोमवार, 7 जुलाई	भाई मक्खन शाह लबाना जंयती
मंगलवार, 15 जुलाई	कवि बाजे भगत जयंती
रविवार, 27 जुलाई	महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती
मंगलवार, 26 अगस्त	श्री गुरु जम्भेश्वर जी जयंती
बुधवार, 17 सितम्बर	भगवान विश्वकर्मा जयंती
शुक्रवार, 31 अक्तूबर	सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती
बुधवार, 12 नवम्बर	संत नामदेव जयंती
शनिवार, 22 नवम्बर	वीरांगना झलकारी बाई जयंती
वीरवार, 4 दिसम्बर	संत सेन भगत महाराज जयंती
शनिवार, 20 दिसम्बर	महाराजा शूरसैनी जयंती

■ राजपत्रित अवकाश ■ वैकल्पिक अवकाश ■ विशिष्ट दिवस

सभी शनिवार एवं रविवार का सार्वजनिक अवकाश।

कर्मचारी तीन वैकल्पिक अवकाश ले सकते हैं।

SAHKAR SE SAMRIDDHI
Aatmanirabhar Bharat, Aatmanirbhar Krishi
NANO TECHNOLOGY
NANO UREA & DAP
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
IFFCO NANO UREA Plus
and
IFFCO NANO DAP
Promises
More Yield And More Profit
World's First Nano Fertilizer by IFFCO
500 ML Bottle ₹225/- only
Contains 20% NITROGEN
FREE ACCIDENT INSURANCE
IFFCO Nano UREA Plus Liquid
NANO UREA PLUS
Chlorophyll Charger
Yield Booster
Climate Smart Farming
500 ML Bottle ₹600/- only
NANO DAP
Nano Di Ammonium Phosphate
LIQUID (8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
Seed Primer | Growth Enhancer | Yield Booster
Less Cost, More Profits
IFFCO Nano DAP Liquid
INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LIMITED
IFFCO Sadan, C-1 District Centre, Saket Place, New Delhi - 110017, INDIA
Phones: 91-11-26510001, 91-11-42592626. Website: www.iffco.coop

दिनांक 21.11.2024 को PWD रेस्ट हाउस, गुरुग्राम में कोरिया हेराल्ड और देवू कॉरपोरेशन के अध्यक्ष तथा कोरिया हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन के चेयरमैन श्री जंग वोन जू की अगुवाई में आए डेलिगेशन के साथ बैठक करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी। साथ में हैं उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह एवं सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा।

जींद सहकारी चीनी मिल के 40वें पेराई सत्र के हवन में आहुति डालकर शुभारम्भ करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा। इस अवसर पर शुगर फेडरेशन के चेयरमैन श्री धर्मबीर सिंह डागर एवं मिल के अधिकारी उपस्थित रहे।

हरियाणा राज्य सहकारी विकास फैडरेशन की ओर से सौरव शर्मा संपादक द्वारा हरियाणा सहकारी प्रैस 165–166, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–1, चण्डीगढ़ से मुद्रित व प्रकाशित तथा कार्यालय बेज नं. 49–52, प्रथम तल, सेक्टर–2, पंचकूला ।
दूरभाष : 0172–2560340, 2560332 हरकोप्रैस : 0172–2637264